जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक:192 दिनांक:17-11-2024 रविवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

मणिपुर सरकार के तीन मंत्रियों और छह विधायकों के आवास का घेराव किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए तोड़फोड़ भी। तीन विधायकों की संपत्तियों को आग लगा दी गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इंफाल घाटी में कर्फ्यू लगा दिया।

एक नवजात शिशु की माँ अपने बेटे की पहचान करने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ चली गई, जिसका इलाज झाँसी जिले के महारानी लामीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद नवजात गहन देखभाल इकाई से बचाए जाने के बाद एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है।

बिना नाम लिए पाकिस्तान को सुना गए पीएम मोदी.....अब आतंकवादी अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पड़ोसी देश के आतंकवादियों के कारण भारत में लोग अपने घरों, शहरों में भी सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब आतंकवादी अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं रह गए हैं। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद से निपटने में सरकार की दृढ़ नीतियों का उल्लेख किया।

पीएम मोदी ने 26-11 मुंबई हमलों की रिपोर्ट का जिक्र कर कहा कि तब आतंकवाद के कारण लोग असुरक्षित महसूस करते थे। अब, हमारी सरकार की कड़ी कार्रवाई और मजबूत सुरक्षा उपायों की वजह से स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति से दूर रहकर देश के विकास को प्राथमिकता देती है।

इसके अलावा, पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर महायुति सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार से काफी प्रभावित हैं, राज्य के लागे चाहते हैं कि यह सरकार अगले पांच साल तक चले।

पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस और उनकी सरकार के बीच अंतर को स्पष्ट कर कहा कि उनकी सरकार सामूहिक प्रगति की कल्पना करती है, जबकि कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने इतिहास से परिचित है और अब इन समुदायों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी उनके खिलाफ ताकतवर नहीं बन सके।

20 नवंबर को मतदान के कारण 6 राज्यों में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी

नई दिल्ली,(ईएमएस)। 20 नवंबर को झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में मतदान होनो है जिसके चलते यहां सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इन राज्यों में स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकें।

झारखंड में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना है यहां दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 12 जिलों के 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 1.23 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे।

वहीं यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवां,खैर,मीरापुर,सीसामऊ,कटेहरी, करहल और कुंदरकी सीटें हैं। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिसमें डेरा बाबा नानक, छब्बेवाल, गिद्दड़बाहा, बरनाला हैं। केरल की एक विधानसभा सीट पलक्कड़, उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट केदारनाथ और महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट नांदेड़ लोकसभा पर मतदान होगा। राज्य सरकारों ने मतदान में नागरिकों की भागीदारी तय करने के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सभी परिणाम 23 नवंबर को आएंगे।

चुनाव आयोग ने अमित शाह और राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर नोटिस जारी किए

नई दिल्ली (ईएमएस)। चुनाव आयोग ने शनिवार अमित शाह और राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर जारी किए हैं। दोनों दलों के अध्यक्षों से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कथित तौर पर दोनों नेताओं की टिप्पणियों में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है।

बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान का सिलसिला खत्म होने से दो दिन पहले सोमवार का दिन शुरू होने, यानी रात एक बजे तक अपने-अपने जवाब देने हैं।

बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने 6 नवंबर को मुंबई में दिए गए भाषण में अन्य राज्यों पर महाराष्ट्र के कथित अवसर चुराने और छीनने का झूठा आरोप लगाया था।

बीजेपी ने 11 नवंबर को की गई शिकायत में कहा, राहुल गांधी अपने बयानों से महाराष्ट्र के युवाओं को भड़का रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है। उनके प्रचार और आचरण के सामान्य पैटर्न के अनुरूप जैसा कि अपेक्षित था, राहुल गांधी का भाषण झूठ और मिथ्या से भरा था, जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों के बीच असंतोष, दुश्मनी और दुर्भावना पैदा करना था। राहुल गांधी ने अपने भ्रामक बयान से महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश की है।

कांग्रेस ने जवाबी शिकायत में आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को धनबाद में एक चुनावी रैली के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बारे में झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए।

कांग्रेस ने 13 नवंबर को अपनी शिकायत में कहा, अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हैं; देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। झारखंड में बीजेपी के अभियान में जो एक आम बात बन गई है, अमित शाह ने कांग्रेस पर एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के सदस्यों से आरक्षण छीनने और उन्हें एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को देने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया है।

यूपी के उपचुनाव में भाजपा के लिए हैं कई चुनौतियां, योगी के बंटोगे तो कटोगे के नारे पर उठे सवाल

लखनऊ(ईएमएस)। राजनैतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। सभी दलों की नजरें इसी राज्य पर होती हैं। अब यहां राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के साथ उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया में ऐसी खूब खबरें आ रही थीं कि पार्टी के भीतर भी यूपी सीएम के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। कहा जा रहा था कि राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर सीधे सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन, पार्टी नेतृत्व ने इस बवंडर को थाम दिया और कहा गया कि सभी को उपचुनाव पर फोकस करना है।

मगर उप चुनाव से ठीक पहले बीते कुछ दिनों से यूपी के प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन और अब झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड में 10 मासूमों की मौत ने राज्य की राजनीति का नैरेटिव अचानक से बदल दिया है। छात्रों आरओ और एआरओ की परीक्षा को दो पारी में कराने और मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। इसको लेकर उनका पांच दिनों से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में छात्रों की भीड़ ने एक बार फिर बेरोजगारी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने छात्रों की कई मांगे मान ली। लेकिन, इसने राज्य में चुनाव से पहले नैरेटिव चेंज कर दिया। फिर मतदान से महज चार दिन पहले झांसी की घटना से राज्य के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा अब केंद्र में आ गई है। विपक्ष इसको लेकर आक्रामक रुख अपना रहा है। ऐसे में सरकार को इन मुद्दों पर बात करनी होगी और बात करने पर सीएम योगी का नारा 'बंटोगे तो कटोगे' का प्रभाव कूंद पड़ेगा।

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद अभेद्य किला में तब्दील हुआ रामलला का मंदिर

अयोध्या (ईएमएस)। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीते दिनों खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आंतकी पन्नू ने वीडियो जारी कर धमकी दी थी कि 16-17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी। खालिस्तानी आंतकी की धमकी के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राम मंदिर के परिसर के चारों तरफ येलो जोन में एटीएस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ एसपी (मंदिर सुरक्षा) ने रूट मार्च किया। इसके साथ ही बैरियर पर तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी वाहनों की सघन चेकिंग करने के बाद ही रामलला के परिसर की तरफ गाड़ियों को प्रवेश दिया जा रहा है।

इतना ही नहीं तकनीकी का प्रयोग करते हुए अयोध्या को अभेद्य किला में बदला गया है। अयोध्या के प्रवेश द्वार से ही सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है। सभी बैरियरों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रामनगरी में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की तलाशी हो रही है। बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड और एटीएस के साथ खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पर हैं। एसपी सुरक्षा बालाचारी दुबे ने बताया कि अयोध्या धाम की सुरक्षा की दृष्टि से सीआरपीएफ, पीएससी, एटीएस, सीआरपी के कमांडो के साथ हम लोगों ने अयोध्या धाम के चारों तरफ चेकिंग कर रहे हैं।

लॉटरी किंग मार्टिन के दफ्तर पर ईडी का छापा, 8.8 करोड़ रुपए बरामद

लॉटरी के जरिए कमाए काले धन को वैध बनाने का है आरोप

चेन्नई ,(ईएमएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के दफ्तर पर छापेमारी की और वहां से 8.8 करोड़ रुपए की राशि बरामद की है। मार्टिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिनमें उन्होंने लॉटरी बेचकर गलत तरीके से रुपया कमाया है। ईडी ने मार्टिन और उनके परिवार के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जो चेन्नई और कोयंबटूर के अलावा फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में स्थित थे। यह छापेमारी पिछले साल मई में की गई एक बड़ी छापेमारी के बाद की गई है, जब ईडी ने मार्टिन और उनके साथियों के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 457 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। इनमें 158 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स और 299 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शामिल थी।

ईडी की जांच मार्टिन द्वारा कई राज्यों में बेची गई लॉटरी से अर्जित धन की प्रकृति और स्त्रोत पर केंद्रित है। उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर सिक्किम राज्य की लॉटरी में धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में, मार्टिन पर आरोप है कि उन्होंने लॉटरी के जरिए बड़ी मात्रा में काले धन को वैध बनाने की कोशिश की।

मार्टिन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक चंदा देने वालों में से एक हैं। उन्हें चुनावी बॉन्ड के जरिए तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी डीएमके समेत कई अन्य पार्टियों को 1,368 करोड़ रुपए का चंदा देने का आरोप है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ हफ्ते पहले ही पीएमएलए के तहत ईडी के खिलाफ किए गए केस को सही ठहराया था। ईडी अब मार्टिन के काले धन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेन-देन और राजनीतिक चंदे के संबंध में भी गहन जांच की जा रही है।

ईडी की इस छापेमारी के बाद से संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में और भी कई राज सामने आ सकते हैं, जिनसे मार्टिन की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पर्दाफाश हो सकता है। इस मामले ने राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि मार्टिन की कंपनी और उसकी गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि ईडी इस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या खुलासा होते हैं।

एक और बाघ की मौत, संकट में आ जाएगा मध्यप्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा

बाघ की मौत ने वन विभाग की लापरवाही उजागर की

भोपाल (ईएमएस)। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत ने वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग को हिल कर रख दिया है। दक्षिणी वन मंडल में एक बाघ की मृत अवस्था में प्राप्त हुई, जिसकी मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम से चला। रिपोर्ट के अनुसार, बाघ को चोट लगने के कारण शिकार करने में असमर्थ हो गया था, और वह कई दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा। बाघ ने जंगल में भोजन की तलाश की, लेकिन अंततः भोजन नहीं मिलने पर अपनी जिंदगी खो दी। यह घटना विशेष रूप से चिंता का विषय बनी है, क्योंकि बाघ का शव एक रिहायशी इलाके के नजदीक मिला था, और आसपास के ग्रामीणों ने बाघ के मूवमेंट की सूचना दी थी। इसके बावजूद, वन विभाग ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। विभाग द्वारा जंगल में पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी की जा रही है, फिर भी घायल बाघ का पता नहीं चल पाया।

जहां एक ओर मध्यप्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, में बाघों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पेंच टाइगर रिजर्व में मई 2024 में एक बाघिन का शव मिला था, बीते कुछ सालों में करंट लगने या अन्य कारणों से बाघों की मौतें सामने आई हैं। 2023 में भी करंट लगाकर एक बाघ का शिकार करने की घटना सामने आई थी।

छग-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 5 नक्सली ढेर

जगदलपुर (ईएमएस)। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर की सरहद से लगे महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। मुठभेड़ अब भी जारी है। वहीं दो जवानों को भी गोली लगी है, जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। कांकेर एसपी आईके एलिसेला ने इसकी पुष्टि की है।

बस्तर के लगभग सभी जिलों के डीआरजी जवान और महाराष्ट्र के सी-60 कमांडोज ने नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर अभय को घेरने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है।

इंफाल में दो मंत्रियों और तीन विधायकों के घरों को लगाई आग

इंफाल (ईएमएस)। जिरीबाम जिले में तीन लोगों की हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी शनिवार को इंफाल में मणिपुर के कम से कम दो मंत्रियों और तीन विधायकों के घरों में घुस गए। विधायकों के घरों पर भीड़ के हमलों के कारण इंफाल पश्चिम प्रशासन को जिले में अनिश्चित काल के लिए निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। अधिकारियों ने इंफाल पश्चिम, पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर में दो दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया है।

इंफाल पश्चिम जिले के सगोलबंद इलाके में आंदोलनकारी भाजपा विधायक आरके इमो के आवास के सामने एकत्र हुए और इस मुद्दे पर सरकार से उचित प्रतिक्रिया की मांग करते हुए नारे लगाए। आरके इमो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने तीन लोगों की हत्या के मामले में अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कीशमथोंग निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक सपम निशिकांत सिंह के टिडिम रोड स्थित उनके आवास पर मिलने आए प्रदर्शनकारियों ने उनके स्वामित्व वाले एक स्थानीय समाचार पत्र के कार्यालय भवन को निशाना बनाया, जब उन्हें बताया गया कि विधायक राज्य में मौजूद नहीं हैं। शुक्रवार रात मणिपुर-असम सीमा पर जिरी और बराक नदियों के संगम के पास तीन शव पाए गए, जिनके बारे में संदेह है कि ये जिरीबाम जिले के छह लापता लोगों के हैं।

जिस प्लेटफार्म पर फेक न्यूज हो उसको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए - अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के हॉल नंबर 6 में ''एमएसएमई मंडप'' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मांझी ने मंडप में विभिन्न प्रदर्शकों से बातचीत की और उन्हें मेले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके साथ एमएसएमई मंत्रालय के डीसी डॉ. रजनीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

मंत्रायल ने कहा कि एमएसएमई मंडप में देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इस बार मंडप का मुख्य विषय ''हरित एमएसएमई'' है, जो एमएसएमई द्वारा अपने व्यवसाय संचालन को बदलने के लिए स्वच्छ यानी हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देता है।

इस दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक 'नुक्कड़ नाटक' भी प्रस्तुत किया गया। ''पीएम विश्वकर्मा योजना'' जिसमें 8 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को अंतिम सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर, 2023 को लॉन्च किया था।

आईआईटीएफ-2024 के 43वें संस्करण में एमएसएमई मंडप में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें कपड़ा, हथकरघा, हस्तशिल्प, कढ़ाई, चमड़े के जूते, खेल और खिलौने, बांस शिल्प, बेंत की वस्तुएं, रत्न और आभूषण, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद, यांत्रिक वस्तुएं आदि शामिल हैं। ये मेला सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), विशेष रूप से महिलाओं और एससी तथा एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमों और आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को संभावित ग्राहकों के एक बहुत बड़े समूह तक बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।

समावेशी विकास के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता के अनुरूप, 200 स्टॉलों में से 71 फीसदी स्टॉल महिला उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं और 45 फीसदी स्टॉल अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों को निःशुल्क आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 35 फीसदी स्टॉल आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं, जिसमें 85 फीसदी से अधिक प्रतिभागी पहली बार भाग ले रहे हैं।

चीन की कर्ज-जाल कूटनीति से फंसते जा रहे पड़ोसी मुल्क भारत के लिए चिंताएं बढ़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के पड़ोसी देशों पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापारिक हितों को चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में चीन के बड़े निवेश और परियोजनाओं ने भारत के लिए रणनीतिक चिंताए पैदा कर दी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) और कर्ज-जाल कूटनीति से ये देश चीन के प्रति अधिक झुकाव दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), नेपाल में नक्शे विवाद, बांग्लादेश में आर्थिक निवेश, और श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर नियंत्रण इसके मुख्य उदाहरण हैं।

भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ा रहा है। क्वाड जैसे संगठन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। साथ ही, भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना और घरेलू रक्षा उत्पादन के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। विश्लेषकों का कहना है कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को पड़ोसी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को और गहरा करना होगा।

भारत की रणनीति : भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह संगठन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सक्रिय है। क्वाड की हालिया बैठक में चीन के खिलाफ आर्थिक, सुरक्षा और सामरिक उपायों पर चर्चा हुई।

चाबहार बंदरगाहः चीन के बढते प्रभाव के बीच भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना है, जो चीन के ग्वादर बंदरगाह का मुकाबला कर सकता है। वहीं रूस, ईरान और अन्य देशों के साथ व्यापारिक और सैन्य संबंध मजबूत कर भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। रेलू रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए सैन्य शक्ति में वृद्धि की जा रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापारिक हितों को चुनौती मिल रही है।

दूल्हा-दूल्हन समेत 7 की मौत

बिजनौर (ईएमएस)। यूपी के बिजनौर में बेकाबू कार ने टेंपो में टक्कर मार दी। टेंपो सडक़ किनारे खाई में जा गिरा। हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दूल्हे की मौसी, मौसा और मौसेरी बहन शामिल हैं। कार सवार 2 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूल्हा-दुल्हन झारखंड से ट्रेन से रात 1:30 बजे मुरादाबाद स्टेशन पर उतरे। वहां से टेंपो में सवार होकर बिजनौर के धामपुर जा रहे थे, तभी नेशनल हाईवे-74 पर कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा फायर स्टेशन के पास में शनिवार रात 2 बजे हुआ। यहां से दूल्हे का घर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। एसपी अभिषेक ने बताया- घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है।

अकाल तख्त की ओर से 'तनखैया घोषित किये गए सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

चंडीगढ़ (ईएमएस)। अकाल तख्त की ओर से 'तनखैया (धार्मिक कदाचार का दोषी) घोषित किये गए सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बादल के इस्तीफे से नये पार्टी प्रमुख के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि बादल ने पार्टी कार्यसमिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज पार्टी की कार्यसमिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, ताकि नये अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने अपने नेतृत्व में विश्वास जताने और पूरे कार्यकाल में तहेदिल से समर्थन तथा सहयोग देने के लिए पार्टी के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार जताया है।''

बादल ने शिअद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले अकाल तख्त के जत्थेदार से धार्मिक कदाचार के आरोपों में उन्हें सजा सुनाने का आग्रह किया था। शिअद नेता ने कहा था कि उन्हें 'तनखैया करार दिए जाने को दो महीने से अधिक समय बीत चुका है।

सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने 2007 से 2017 तक अकाली दल और उसकी सरकार की ओर से की गई ''गलतियों'' के लिए बादल को 30 अगस्त को ''तनखैया'' घोषित किया था। जत्थेदार ने अभी तक बादल के लिए ''तनखा'' (धार्मिक सजा) की घोषणा नहीं की है।

बादल के अकाल तख्त से कोई अस्थायी राहत पाने में नाकाम रहने के बाद शिअद ने 24 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह उपचुनाव नहीं लड़ेगा। एक जुलाई को पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की पूर्व प्रमुख बीबी जागीर कौर सहित कई बागी शिअद नेता अकाल तख्त के सामने पेश हुए थे। उन्होंने 2007 से 2017 तक पार्टी की सरकार की ओर से की गई ''गलतियों'' के लिए माफी मांगी थी।

मुंबई में 80 करोड़ रुपये की चांदी बरामद

मुंबई, (एईएमएस)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के साथ पुलिस भी राज्य की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। इस बीच मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 8 हजार 476 किलो चांदी जब्त की है। इस चांदी की कीमत करीब 80 करोड़ रुपये है। इतनी बड़ी मात्रा में चांदी देखकर पुलिस और चुनाव अधिकारी भी हैरान रह गए। चुनाव के दौरान नकदी और अवैध सामान जब्त करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मानखुर्द पुलिस ने वाशी चेकनाका इलाके में नाकाबंदी कर रखी थी। पुलिस यहां आने-जाने वाले हर वाहन की जांच कर रही थी। शुक्रवार देर रात एक संदिग्ध ट्रक वाशी चेकनाका से गुजर रहा था। पुलिस ने ट्रक को रोककर जांच की।

इस ट्रक में भारी मात्रा में चांदी देखकर अधिकारी हैरान रह गए। जब इस चांदी का वजन किया गया तो यह कुल 8 हजार 476 किलोग्राम निकली। इस चांदी की कीमत सर्राफा बाजार में करीब 80 करोड़ रुपये है। इस घटना के बाद पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने घटना की सूचना आयकर विभाग और चुनाव आयोग को भी दी। आयकर विभाग अब जब्त चांदी के स्वामित्व की जांच कर रहा है। प्रारंभिक जांच में संदेह है कि चांदी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। चुनावी मौसम को देखते हुए आयकर विभाग और चुनाव आयोग ने इस तरह की घटना को गंभीरता से लिया है। इस बीच, यह जांच की जा रही है कि चांदी के परिवहन के लिए कोई कानूनी दस्तावेज हैं या नहीं। पुलिस ने कहा कि किसी भी अवैध संपत्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, इससे क्षेत्र के नागरिकों में तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गयी है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि अगर जब्त चांदी का मालिक कौन है इसका आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला तो पूरी चांदी सरकारी खजाने में चली जाएगी। फिलहाल जांच अभी चल रही है।

आसियान सम्मेलन में मिलेंगे दोनों नेता

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 नवंबर को चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात अगले हफ्ते लाओस में होने वाले आसियान सम्मेलन में होगी। पिछले महीने पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने और पिछले हफ्ते भारतीय सेना के देपसांग इलाके में फिर से गश्त शुरू करने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी।

अप्रैल 2023 के बाद पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिल रहे हैं। इससे पहले चीन के तत्कालीन रक्षा मंत्री ली शांगफू शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आए थे। पिछले महीने रूस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इसके बाद अब यह बैठक होगी।

दरअसल, भारत-चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चार साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। दो साल की लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी।

पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हुए रवाना ,वैश्विक साझेदारी की नई दिशा तय करेगी नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना यात्रा

नई दिल्ली,(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यह दौरा भारत की वैश्विक भागीदारी और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा पहली यात्रा है, जिसे प्रधानमंत्री ने पश्चिम अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को मजबूत करने का अवसर बताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नाइजीरिया में बसे भारतीय समुदाय से मुलाकात की उत्सुकता व्यक्त की।

जी-20 शिखर सम्मेलन, ब्राजील

विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्राजील में आयोजित होने वाले 19वें जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष भारत ने जी-20 की सफल अध्यक्षता की थी। इस वर्ष ब्राजील एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के तहत भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने जी-20 को जनता का जी-20 बनाया, जिसमें वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को प्राथमिकता दी गई।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा गुयाना में 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। म

जन हितैषी

1 वर्ष में सड़क हादसों में 1,72,890 लोगों की मौत, 9489 नाबालिग

भारत में रोजाना सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2023 में 172890 लोगों की मौत हुई है। 4 लाख 80 हजार 513 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। भयंकर रूप से जख्मी लोगों की संख्या 462825 थी। 18 वर्ष से कम उम्र के तथा बिना हेलमेट पहने जिन लोगों की सड़क दुर्घटना में मौतें हुई है। उनकी संख्या 54568 थी। सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक राजस्थान बिहार आंध्र प्रदेश और गुजरात में सर्वाधिक मोतें हुई हैं। किसी भी देश में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। पिछले दो दशक में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। केंद्र सरकार की लापरवाही इन दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। पिछले दो दशक में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जो राजमार्ग बनाए गए हैं। उनमें काफी स्पीड से वाहन चलते हैं। जो वाहन पिछले 20 वर्षों में तैयार किये जा रहे हैं।उनकी स्पीड पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। वाहन निर्माता द्वारा जो लाइटें वाहनों में लगाई जा रही हैं। वह काफी दूर तक तेज रोशनी फेंकती हैं। जिसके कारण सामने वाले वाहन के चालक को कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है। सड़कों पर वाहन 100 से लेकर 120 किलोमीटर की रफ्तार में चलाए जा रहे हैं। लाइट के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं रात के समय में हो रही हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय दुर्घटनाओं का ठीकरा हेलमेट के ऊपर फोड़कर दुर्घटना से बचाव करता है। चार पहिया वाहनों में अब पैसेंजर के लिए बेल्ट के माध्यम से वाहनों में सुरक्षा बेग से सुरक्षित होने की बात बड़ी जोर-जोर से प्रचारित करता है। लेकिन जब दुर्घटनाएं होती हैं, तो यह बेग भी वाहन चालकों और वाहन में बैठे हुए यात्रियों को कोई सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं । जिस तेजी के साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वाहनों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। उसके हिसाब से वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के कोई इंतजाम भारत में नहीं किए गए हैं। वाहनों में जो लाइटें लगाई जा रही हैं। वही दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। वाहन जब सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। अधिकांश दुर्घटनाओं में यह पय गया है, कि वाहन चालक अपना नियंत्रण नहीं रख पाया। सड़कें भी जिस तरीके से बनाई गई हैं। वह भी दुर्घटना स्पाट के रूप में सामने आ रही हैं। गलत डिजाइनिंग और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती ही चली जा रही हैं। कुछ समय पहले वाहनों में जो लाइट लगाई जाती थी। उनमें अपर डिपर और लाईटें इस तरह से लगाने की व्यवस्था की जाती थी। सामने वाले वाहन चालक के आंखों में सीधी रोशनी ना पड़े। लेकिन अब जिस तरीके से वाहनों में लाइट लगकर आ रही हैं। उसकी लाइट सामने वाले वाहन चालकों पर सीधी पड़ती है। जो वर्तमान में वाहन चालक हैं।वह अपर-डिपर से लाइट को कंट्रोल करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। जिसके कारण वाहन दुर्घटनाओं की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़कर लाखों पर पहुंच गई है। लाखों लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है। लाखों लोग अस्पताल में गंभीर रूप से घायल होकर कई महीनौं और वर्षों तक इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सारे जीवन अपाहिज की तरह अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर होते हैं। पिछले 20 वर्षों से भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले लोगों की मौत की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हेलमेट नहीं पहनने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भारी जुर्माना सड़कों पर खड़ी पुलिस द्वारा वसूल किया जा रहा है। जुर्माने से सरकार को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है।लेकिन सड़क दुर्घटनाएं और इसमें मरने वालों की संख्या कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है।जुरमाने से सरकार वाहन दुर्घटनाओं को रोकने की जो कवायत कर रही है। उससे सरकार को कमाई तो हो रही है। लेकिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लगता है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में सरकार विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। यदि ऐसा नहीं है, तो फिर क्या कारण है, हर साल सड़क दुर्घटनाओं मैं रोकथाम नहीं हो पा रही है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की अक्षमता से जोड़ा जा सकता है। परिवहन मंत्रालय वाहनों के निर्माण, तकनीकी, रोड निर्माण की तकनीकी, डिजाइन तथा वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम बनाती है। एक आम आदमी भी यह कह रहा है। तेज गति से चलने वाले वाहन की लाइट के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क पर खड़े हुए वाहनो से तेज गति से आ रहे वाहन भिड़ रहे हैं। वाहन चालकों को रात मे दिखते नहीं है। जो गंभीर दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। इसी तरह सड़कों पर मवेशी बैठे रहते हैं। वह भी दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण हैं। इन सारी स्थितियों पर सरकार को विचार करके सभी मामलों को नियंत्रित करने होंगे। अन्यथा सड़क दुर्घटनाएं इसी तरह से बढ़ती रहेगी। रोक लगाने के जो भी प्रयास किया जा रहे हैं। वह सभी अभी तक असफल साबित हुए हैं।

कौन लेगा इन नवजात शिशुओं की मौत की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में हुए अग्निकांड ने प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश को हिलाकर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाले अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 मासूमों की हालत नाजुक बताई गई है। अस्पताल ने जानकारी दी कि एनआईसीयू में कुल 54 नवजात शिशु भर्ती थे। बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थेख् जिस कारण यह दर्दनाक अंग्निकांड मासूमों की मौत का कारण बना। भयावह आग कैसे लगी यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन आग न लगे और आग लगने पर बुझाने और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम पहले से क्यों नहीं थे, यह जरुर शासन-प्रशासन की लचर व्यवस्था को उजागर करने के लिए काफी है। सबसे गंभीर और विचारणीय बात यह है कि इस घटना के बाद मालूम चला कि अस्पताल का फायर अलार्म और वॉटर स्प्रिंकलर ने काम ही नहीं किया, जिससे बचाव कार्य समय पर शुरु नहीं किया जा सका। अस्पताल के फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी हालत में थे और आग बुझाने के वैकल्पिक इंतजाम का कोई अता-पता नहीं था। मतलब यह कि सब भगवान भरोसे चल रहा था।

यह हादसा न केवल उन परिवारों के लिए एक अपार दुःख का कारण बना, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, बल्कि आधुनिक समाज और चुस्त प्रशासन के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था और अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में भी अस्पतालों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय हैं? क्या कर्मचारियों को इस प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया गया है? क्या आवश्यक चिकित्सा उपकरण और प्रणालियाँ सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं? ये वे सवाल हैं, जिनका उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ ही साथ समाज के जिम्मेदारों को भी देना होगा। किसी बड़ी दुर्घटना होने के बाद जैसा कि होता आया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। मृतकों के परिजनों समेत घायलों के इलाज के लिए मुआवजे की घोषणाएं भी हो रही हैं। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अनेक नेताओं समेत अनेक राजनीतिक हस्तियों ने इस घटना पर गहरा शोक भी व्यक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हृदयविदारक घटना करार दिया है, जिससे समझा जाना चाहिए कि अब आगे से ऐसा न हो, इस पर गंभीरता से न सिर्फ विचार किया जाएगा बल्कि इंतजाम भी बेहतर किए जाएंगे और मासूमों की मौत जो हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी उच्च स्तर पर तय कर दोषियों को वाकई सजा दी जाएगी। संपूर्ण देशवासियों की संवेनाएं पीड़ित परिवारों के प्रति है। इसी मानवीयता के साथ आगे इस तरह की अन्य कोई घटना न हो, इस पर जरुर काम होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी जरुरी है, क्योंकि फिर विपक्ष के पास इस तरह के हादसे को लेकर प्रशासन की लापरवाही और राज्य सरकार की विफलताओं को रेखांकित कर निशाना साधने का अवसर भी नहीं रहेगा।

यह हादसा न केवल एक चिकित्सा संस्थान की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह एक गंभीर चेतावनी भी है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही ऐसे संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की महति आवश्यक्ता है। यह घटना प्रशासनिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों को उजागर करती है, जिनकी वजह से उन मासूमों की जान चली गई, जिन्होंने इस दुनियां में तो पदार्पण किया, लेकिन ठीक से आंख खोलकर भी नहीं देखा कि वो किस नर्क में आ गए। ये वो नौनिहाल थे, जो आगे चलकर देश का भविष्य बेहतर करने में अपनी सहभागिता निभा सकते थे, लेकिन अफसोस कि हमारे कठोर होते तंत्र ने उन्हें किसी दुर्घटना से बचाने का माकूल इंतजाम तक नहीं किया। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि सरकार और प्रशासन तत्काल प्रभाव से ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम जरुर उठाएंगे। इस त्रासदी ने देश को झकझोर कर रख दिया है और इस समय पूरे देश की नजर उन परिवारों की तरफ है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और यह भी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। (लेखक- डॉ हिदायत अहमद खान / ईएमएस)

देश के लिये कलंक है मिलावटी व नक़ली खाद्य सामग्री का चलन

कम से कम समय व लागत में अधिक से अधिक धन कमाने जैसी शार्ट कट मानवीय प्रवृति ने लगभग पूरे देश को संकट में डाल रखा है। भारतीय बाज़ार में नक़ली व मिलावटी सामानों की भरमार इसी प्रवृति का नतीजा है । परन्तु जब यही मिलावटख़ोरी या नक़ली सामग्री का इस्तेमाल खाद्य सामग्रियों में होने लगता है तो निःसंदेह यह सीधे तौर पर इंसान की जान से खिलवाड़ करने या धीमा ज़हर देने के सिवा और कुछ नहीं। पूरा देश इस बात से भली भांति वाक़िफ़ है कि हमारे देश में दूध का जितना उत्पादन होता है उससे कई गुना ज़्यादा दूध व दूध से बनी ज़रूरी सामग्री की खपत होती है। यह दूध आख़िर कहाँ से आता है ? सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में ऐसी अनगिनत वी डी ओ वायरल हो चुकी हैं जिनमें नक़ली व ज़हरीला दूध बनते देखा जा सकता है। नक़ली व मिलावटी देसी घी,खोया सब कुछ देश में बन रहा है व बेचा जा रहा है। असली नक़ली का भेद न कर पाने वाली आम जनता उसी धीमे ज़हर को खाने पीने के लिये मजबूर है। और इन्हीं या इनसे बनी अनेक खाद्य सामग्रियों का सेवन कर तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रही है।

अब तो हद यह हो गयी है कि पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली ,ग़ाज़ियाबाद,मोदीनगर और हरियाणा के जींद से अमूल जैसे लोकप्रिय देसी घी सहित कई अन्य कम्पनीज़ के ब्रांड के नाम पर बनने वाला नक़ली घी पकड़ा गया। ज़हरीली खाद्य सामग्री का व्यवसाय करने वाले यह लोग टेट्रा पैक पर अमूल घी, मधुसूदन घी, मदर डेयरी घी, पतंजलि गाय घी, वर्का घी, नेस्ले एवरीडे घी, आनंद घी, परम देशी घी, मिल्कफूड देशी घी, मधु घी, लक्ष्य घी और श्वेता घी जैसी कम्पनीज़ के नक़ली ब्रांड पैक इस्तेमाल करते थे। और इन्हीं अलग अलग कंपनी के ब्रांड नाम से तैयार किया जा रहा देसी घी बनाकर बाज़ार में बेच रहे थे। केवल हरियाणा के जींद में जो देसी घी बनाने वाली फ़ैक्टरी पकड़ी गई है वहां 2500 लीटर नक़ली घी का कच्चा माल बरामद हुआ। पुलिस ने इस मिलावटी नेटवर्क को चलाने में रितिक खंडेलवाल,मथुरा,संजय बंसल, शाहदरा, दिल्ली,रोहित अग्रवाल,मोदीनगर, गाज़ियाबाद,कृष्ण गोयल,जींद, नरेश सिंघला व अश्वनी उर्फ आशु,जींद को आरोपी बनाया है। नक़ली ज़हरीला घी खाने का अर्थ कैंसर को दावत देना होता है। वैसे तो देसी घी में प्रायः आलू, शकरकंद जैसे स्टार्च की मिलावटी की जाती है। लेकिन कई बार इसमें कोल टार डाई या अन्य ख़तरनाक रसायन भी मिला दिये जाते हैं जिसके कारण फ़ूड पॉइज़निंग , एलर्जी जैसी परेशानियों से लेकर कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी तक भी हो सकती है।

ख़बरों के अनुसार गत 12 नवंबर (मंगलवार) को केवल दिल्ली में एक ही दिन में 50 हज़ार शादियां हुईं। ज़रा सोचिये कि हर शादी में दूध घी पनीर खोया मिठाई आदि की कितनी खपत हुई होगी। इसी तरह पूरे देश के विवाह आयोजनों व अन्य समारोहों में आप जब जहाँ और जितना भी घी,दूध,दही मक्खन,खोया,पनीर आदि जो भी चाहें आप को मिल जायेगा। सवाल यह है कि जब सरकार व प्रशासन भी इस जालसाज़ी व मिलावटख़ोरी की ख़बरों व इसके नेटवर्क से वाक़िफ़ है और इसे रोकने के लिये पर्याप्त क़ानून भी बने हैं उसके बावजूद मिलावटख़ोरी का यह सिलसिला दशकों से क्यों चला आ रहा है ? कुछ लोगों की अधिक धन कमाने की शॉर्टकट प्रवृति ने आख़िर पूरे देश को धीमा ज़हर खाने के लिये क्यों मजबूर कर दिया है। क्यों ज़हर के इन व्यवसायियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यह जानने के लिये पड़ोसी चीन की एक घटना का उल्लेख करना ज़रूरी है। कुछ वर्ष पूर्व चीन में अपराधी मानसिकता के ऐसे ही दो लोगों द्वारा नक़ली दूध बनाने का धंधा शुरू किया गया। कुछ दिनों में ही यह नक़ली दूध जांच के दायरे में आ गया। जब यह नेटवर्क ध्वस्त हुआ तो वहां की सरकार ने इन दोनों ही अपराधियों को सज़ा-ए-मौत दे दी। तब से आजतक वहां नक़ली दूध के किसी दूसरे नेटवर्क ने अपना सिर बुलंद नहीं किया।

हमारे देश में इस तरह के नक़ली,मिलावटी व ज़हरीले खाद्य नेटवर्क को बढ़ावा देने के पीछे सच पूछिए तो सरकार,प्रशासन व जनता,कुछ न कुछ सभी ज़िम्मेदार हैं। यदि आप देश के समाचारपत्रों पर नज़र डालें तो शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिसदिन इस तरह का नक़ली,मिलावटी व ज़हरीला खाद्य सामग्री का नेटवर्क पकड़ा न जाता हो। परन्तु आपको यह ख़बर बहुत कम बल्कि ना के बराबर पढ़ने को मिलेगी कि अमुक नक़ली,मिलावटी खाद्य नेटवर्क से जुड़े लोगों को सख़्त सज़ा हुई हो। इसका कारण है कि जो प्रशासन मिलावटख़ोरी के नेटवर्क को पकड़े जाने की वाहवाही जिस तरीक़े से लूटता है वही उनसे जुड़े उन सुबूतों को अदालत तक उस मुस्तैदी के साथ नहीं पहुंचा पाता जैसा कि छापेमारी के समय मीडिया में नज़र आता है। अब चूँकि आदालतें साक्ष्य,गवाही व दस्तावेज़ों के आधार पर ही अपने फ़ैसले सुनाती हैं और अदालत में साक्ष्य,गवाही व दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराना कार्यपालिका का विषय है, इसलिये साक्ष्य,गवाही व दस्तावेज़ों के अभाव में सभी गिरफ़्तार आरोपियों को सज़ा नहीं मिल पाती। इसीलिये यह आम धारणा बन चुकी है कि इसतरह के नेटवर्क से जुड़े लोग भ्रष्टाचार व रिश्वत के दम पर स्वयं को बचा ले जाते हैं और ज़ाहिर है कि बरी होने के बाद यही लोग बुलंद हौसले के साथ आम लोगों को ज़हर बेचने का यही काम फिर शुरू कर देते हैं।

जनता इसलिये ज़िम्मेदार है कि वह ऐसे अपराधियों को समाज में संरक्षण देती है। जो लोग नक़ली,मिलावटी खाद्य नेटवर्क से जुड़े होते हैं वे एलियन नहीं न ही वे आसमान से टपकते हैं । वे भी किसी गली मोहल्ले कॉलोनी या शहरों व गांव में रहते हैं। जब यह लोग ज़हर बेचते पकड़े जाते हैं तो इनके रिश्ते नातेदार पड़ोसी सभी को इनके करतूतों का पता चलता है। वास्तव में समाज को ऐसे लोगों का पूर्णतः सामाजिक बहिष्कार करना चाहिये। यदि अपनी चालाकियों या रिश्वत के बल पर यह अदालत से बरी भी हो जाएँ तो भी पास पड़ोस के लोगों व इनके सभी जानने वालों को इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिये। आश्चर्य है कि जो लोग समाज को ज़हर देकर मारने का संगठित व इरादतन अपराध करते हों उसी समाज के लोग इन अपराधियों को अपने सर माथे पर बिठाते हैं ? इससे भी इनके हौसले बुलंद होते हैं। और ऐसे ही लोगों के चलते मिलावटी व नक़ली खाद्य सामग्री का बढ़ता चलन देश के लिये कलंक बनता जा रहा है। (ले?खिका - निर्मल रानी/ईएमएस)

महाराष्ट्र नहीं अब मणिपुर की फ़िक्र कीजिये माई-बाप

हे ईश्वर ! आप भाजपा को बिना किसी अवरोध के झारखण्ड और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जितवा दीजिये ताकि केंद्र की सरकार इन दोनों राज्यों की फ़िक्र छोड़कर डेढ़ साल से भस्मीभूत हो रहे मणिपुर को राख होने से बचा सके। मणिपुर में हालात जम्मू- काश्मीर से भी ज्यादा भयावह और अकल्पनीय हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गत गुरुवार 14 नवंबर, को मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर पांच जिलों में छह पुलिस थानों की सीमाओं को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) को फिर से लागू कर दिया है।

केंद्र की मशीनरी वोट पाने के लिए महाराष्ट्र में गड़े मुर्दे उखाड़ रही है तो झारखण्ड के आदिवासियों को खुश करने के लिए दिल्ली में सूफी संत काले खान के नाम पर बनी सराय पर बिरसा मुंडा का नाम चस्पा कर रही है। चुनाव जीतने के लिए केंद्र को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हैलीकाप्टर से उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है ,तो धड़ाधड़ ईडी के छापों के जरिये मतदाताओं को हड़काने की कोशिश की जा रही है ,लेकिन मणिपुर की फ़िक्र किसी को नहीं है। जम्मू-कश्मीर की फ़िक्र वहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा पहले ही छोड़ चुकी है।

महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनावी शोरगुल में मणिपुर की आग और वहां की जनता की चीख-पुकार किसी को सुनाई ही नहीं दे रही। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है ही नहीं और यदि है तो ठीक वैसे ही है जैसे किसी जमाने में रूस में साइबेरिया होता था। आपको बता दें कि जो सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए)मणिपुर में लागू किया गया है वो सशस्त्र बलों को बेलगाम शक्ति देता है, स्थानीय जनता शुरू से इस अधिनियम के खिलाफ रही है। जहां तक मुझे याद है कि अप्रैल 2022 में मणिपुर सरकार की ओर से बेहतर सुरक्षा स्थिति और आम जनता के बीच सुरक्षा की बड़ी भावना के बीच इन क्षेत्रों से हटा लिया गया था. अब स्थिति बिगड़ने पर इसे फिर से लागू किया गया है. नया आदेश 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

पता नहीं क्यों देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से कतरा रहे है। उन्हें दरअसल चुनावों से ही फुरसत कहाँ मिल रही है ? पहले जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव ,फिर महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव और इनसे फारिग होते ही बिहार और दिल्ली विधानसभा के चुनावों में उन्हें लगना है। हमारी सरकार ये हकीकत समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मणिपुर को सशत्र बलों की नहीं बल्कि उन नारेबाजों कि जरूरत है जो इस समय महाराष्ट्र और झारखण्ड में बंटोगे तो काटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे का आव्हान करते घूम रहे हैं। मणिपुर की तरह महाराष्ट्र और झारखण्ड में सुरक्षा इतनी बड़ी समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के अग्निमुखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में यदि जरा भी साहस है, विवेक है ,बुद्धि है तो उन्हें तत्काल महाराष्ट्र और झारखण्ड कि चिंता छोड़कर मणिपुर कूच करना चाहिए।

महाराष्ट्र और झारखण्ड में नेताओं के आगे-पीछे घूमने वाला मीडिया भी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तरह मणिपुर जाने से घबड़ाता है। हमारा बहादुर मीडिया यूक्रेन युद्ध कव्हर करने जा सकता है । अमेरिका के रष्ट्रपति चुनाव का कव्हरेज करने जा सकता है , इजराइल-लेबनान युद्ध दिखने जा सकता है ,लेकिन मणिपुर नहीं जा सकत। हिमत ही नहीं है किसी में। आपको किसी टीवी चैनल ने शायद ही ये खबर दी हो कि मणिपुर के जिरीबाम जिले में पांच दिन पहले 11 नवंबर को सैनिकों की वर्दी पहनकर आए उग्रवादियों ने एक पुलिस थाने और निकटवर्ती सीआरपीएफ शिविर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। इस एनकाउंटर के अगले दिन यानी 12 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों ने जिले से महिलाओं और बच्चों सहित छह नागरिकों को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव और बढ़ गया है। 7 नवंबर से शुरू हुई हिंसा में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें तीन पुरुष और महिलाएं शामिल है। हारकर हालात बिगड़ते देख केंद्र सरकार ने यहाँ पुराना क़ानून लागू करने का फैसला किय।

सवाल ये है कि सरकार मणिपुर को लेकर जो नीति अपना रही है उससे क्या मणिपुर की हिंसा समाप्त हो जाएगी ? मणिपुर 3 मई 2023 से हिंसा की आग में जल रहा है। यानि मणिपुर को जलते हुए पूरे 18 महीने हो चुके हैं। इस हिंसा की वजह से करीब 50 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कुकी और मैतेई के बीच चल रहे इस जातीय संघर्ष में अब तक 200से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है,लेकिन देश के प्रधनमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को एक दिन के लिए भी मणिपुर जाने की फुरसत नहीं मिली ,हालाँकि इस बीच वे तीसरी बार सत्ता में भी आ गए । दो बार रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए विदेश दौरे भी कर आये। लोकसभा में विपक्ष के नेता जब इस पद पर नहीं थे तब भी दो बार मणिपुर गए लेकिन उनके हाथ में सिवाय पीड़ितों के प्रति संवेदना जताने के कुछ था ही नही। हाँ उनके पास वो साहस जरूर था जिसका नितांत अभाव महाबली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और देश के गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह जी में बहुत ज्यादा है। तकलीफ इस बात से भी है कि केंद्र मणिपुर की नाकारा सरकार को अभयदान देकर बैठी है सो अलग। केंद्र करे भी तो क्या करे सूबे की सरकार उसकी अपनी जो है।

भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति कोई नया मामला है। इससे पहले भी देश ने अरुणाचल ,असम, नागालैंड में ऐसे ही दौर देखे हैं,लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इन सभी समस्याओं को निबटाया। आज की सरकार तो मणिपुर के मामले में पूरी तरह से नाकाम हुई है । जम्मू-काश्मीर और केरल को लेकर कश्मीर फ़ाइल और केरल फ़ाइल जैसी फ़िल्में बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म निर्माता मणिपुर का सच और सरकार की नाकामी पर फिल्म बनाने का साहस जुटा नहीं पा रहे हैं। देश कि सांसद 25 नवंबर से फिर बैठने वाली ह। देखना है कि सरकार किस मुंह से इस सांसद में मणिपुर को लेकर बोलती है ? (लेखक - राकेश अचल / ईएमएस)

सबसे पुराना बौद्ध धर्म मानने वाला देश है, श्रीलंका

थेरवाद बौद्ध धर्म इस द्वीप का प्रमुख धर्म है, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के सम्राट अशोक के पुत्र आदरणीय महिंदा ने राजा देवनम्पिया-तिस्सा के शासनकाल में आधिकारिक रूप से पेश किया था। बाद में, अशोक की बेटी, भिक्षुणी संघमित्रा ने मूल बोधि वृक्ष की दक्षिणी शाखा को लाया, जहाँ इसे अनुराधापुरा में लगाया गया था। उस दिन से लेकर आज तक, श्रीलंका में बौद्धों ने बोधि वृक्ष की इस शाखा को अत्यधिक श्रद्धा दी है और दे रहे हैं, जिसकी छाया में गुरु को ज्ञान प्राप्त हुआ था।श्रीलंका के भिक्षुओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया में थेरवाद और महायान दोनों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका में ही, पहली शताब्दी ई. में राजा वट्टा गामिनी के शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षु अलोका-विहार में एकत्र हुए और त्रिपिटक, शिक्षाओं की तीन टोकरी लिखी, जिसे पहली बार पाली शास्त्र के रूप में जाना जाता है। यह श्रीलंकाई भिक्षुणियाँ ही थीं जिन्होंने 433 ई. में चीन में भिक्षुणियों के संघ की शुरुआत की। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और उनके बाद आए डच लोगों की तरह बौद्ध धर्म को क्रूरतापूर्वक सताया। 19वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने नियंत्रण हासिल किया तो बौद्ध धर्म काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, ऐसी स्थिति ने अंग्रेज़ मिशनरियों को प्रोत्साहित किया जो फिर द्वीप पर आने लगे। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत मठवासी और आम समुदाय ने 1860 के बाद से एक बड़ा पुनरुत्थान लाया, एक ऐसा आंदोलन जो बढ़ते राष्ट्रवाद के साथ-साथ चला।तब से बौद्ध धर्म फला-फूला है और श्रीलंकाई भिक्षुओं तथा प्रवासी आम लोगों ने एशिया, पश्चिम और यहां तक कि अफ्रीका में भी थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।बौद्ध जगत के कुछ सबसे अद्भुत स्मारक श्रीलंका के हैं, और उनकी मूर्तिकला कृष्णा घाटी की प्रारंभिक कला और बाद के पल्लव और चोल राजाओं के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, क्योंकि दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ संबंध थे।

अनुराधापुरा के पास मठवासी इमारतों के निर्माण की देखरेख की। साथ ही, उन्होंने अवशेषों के लिए भारत भेजा। इतिहास के अनुसार, इनमें बुद्ध का भिक्षापात्र और उनका दाहिना कॉलरबोन शामिल था। बाद में एक बाल अवशेष, और चौथी शताब्दी ईस्वी में, बुद्ध के दांत को श्रीलंका ले जाया गया। दांत अभी भी कैंडी में संरक्षित है, जहाँ दैनिक अनुष्ठानों में बुद्ध के दांत अवशेष की पूजा की जाती है, जो कैंडी के दांत अवशेष मंदिर में 16वीं शताब्दी में हुआ था।अवशेषों को रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित, रुवानवेलिसेया या महान स्तूप को उत्तर-मध्य श्रीलंका में अनुराधापुरा में सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक माना जाता है: काफी हद तक बहाल, पुराने स्तंभों से घिरा महान गुंबद, अभी भी अनुराधापुरा में देखा जा सकता है, जो अब एक बड़ा पार्क है। प्रमुख त्योहारों के दौरान यह परिवार के समूहों में सैकड़ों हज़ारों भक्तों से भरा होता है, जो खंडहरों के बीच खुशी से पिकनिक मनाते हैं और बोधि वृक्ष पर पूजा करते हैं। मिहिंताले में पास में अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जो महिंदा द्वारा राजा देवनमपिया-तिस्सा को दिए गए पहले उपदेश का स्थल है। पोलोन्नारुवा (9वीं शताब्दी ईस्वी के बाद) में बाद की राजधानी के खंडहर, हिंदू और महायान पंथ के प्रभाव को दर्शाते हैं, फिर भी अधिक विस्तृत हैं।

श्रीलंका में स्तूप एक वर्गाकार आधार पर एक गोलाकार ड्रम है, जिसमें एक बक्से के आकार के हर्मिका के ऊपर शंक्वाकार शीर्ष बनाने वाली संपीड़ित छतरियों की एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें से अनुराधापुरा (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) में रुवानवेलिसेया स्तूप एक अच्छा उदाहरण है।(लेखक- संजय गोस्वामी / ईएमएस)

सैमसन, तिलक ने खेली 210 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी

जोहान्सबर्ग,(ईएमएस)। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया को एक विकेट के नुकसान पर 283 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। दोनों के बीच 210 रनों की साझेदारी हुई जिसके लिए उन्होंने 86 गेंदें खेलीं। यह भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी सबसे बड़ी साझेदारी है। दूसरे विकेट के लिए भी यह ओवरऑल बेस्ट पार्टनरशिप रही।

इन्होंने खेली भारत के लिए बड़ी साझेदारी

210* - सैमसन/तिलक बनाम साऊथ अफ्रीका

190* - रोहित/रिंकू बनाम अफगानिस्तान

176 - हुडा/सैमसन बनाम आयरलैंड

173 - सैमसन/सूर्या बनाम बांग्लादेश

165 - रोहित/राहुल बनाम श्रीलंका

165 - जयसवाल/गिल बनाम वेस्टइंडीज

160 - रोहित/धवन बनाम आयरलैंड

158 - रोहित/धवन बनाम न्यूजीलैंड

शब्द पहेली - 8190

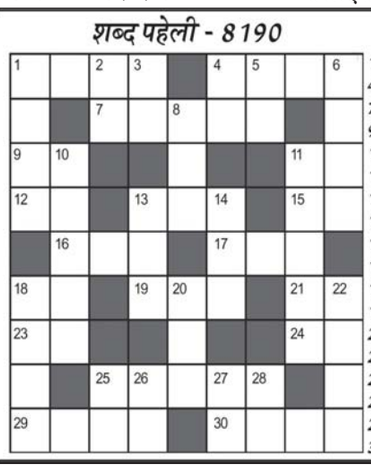

बाएँ से दाएँ

1.जनमत-4
4.सचेत,सजग-4
7. सहयात्री,संगी-5
9.रुपया,पैसा -2
11.छोटी सवारी गाड़ी-2
12.घ्राणेंद्रिय-2
13.बेकार-3
15.झुका हुआ-2
16.बसंत काल-3
17.टिड्डा-3
18.अन्वेषण,ढूंढना-2
19.जलने की प्रक्रिया-3
21.एक वि

डरने की जरुरत नहीं निवेशक को.....बहुत जल्द नए रिकार्ड बनाएगा भारतीय शेयर बाजार

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय शेयर बाजार के बारे में एक बाजार जानकार ने एक अहम भविष्यवाणी की है। जानकार ने कहा कि जब विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) वापस आएंगे, तब निफ्टी इंडेक्स 30,000 तक पहुंच सकता है। बाजार जानकार का मानना है कि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद और विकास क्षमता एफआईआई को आकर्षित करेगी, जो भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए वापस लौट सकते हैं। हाल ही में, चीन की ओर बढ़ते हुए विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से पैसा निकाला, जिसके बाद भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया, इसके बाद कई विदेशी निवेशक चीनी बाजारों में निवेश करने लगे। लेकिन जानकार का मानना है कि यह केवल एक अस्थायी रुझान है और एक बार जब एफआईआई की भारत में वापसी होगी, तब निफ्टी इंडेक्स के लिए नया बुल रन शुरू हो सकता है।

जानकार ने भारत को अमेरिका के साथ दुनिया के केवल दो ग्लोबल बाजारों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार हमेशा अपने निवेशकों को भरोसेमंद रिटर्न प्रदान करता है और यह बाजार दीर्घकालिक निवेश के लिए बेहतर है। उन्होंने स्वीकार किया कि हमेशा निवेशक चीन और कोरिया जैसे अन्य एशियाई बाजारों में डायवर्सिफिकेशन लाते हैं, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास की गति फिर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगी। भारतीय निवेशकों को सलाह दी कि वे बाजार के उतार-चढ़ाव से डरने के बजाय पूरी तरह से निवेश बनाए रखें। उनके अनुसार, भारत की ऊंची कंपाउंडिंग क्षमता को देखते हुए लंबी अवधि के निवेश से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, निवेशित रहें और कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दें।

वोडाफोन आइडिया पर गहराया संकट, ए जी आर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

मुंबई (ईएमएस)। वोडाफोन आइडिया (वीआई) को 25,000 करोड़ के डेट फंडिंग प्लान में देरी के कारण बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद संकट और बढ़ गया है। वीआई पर एजीआर बकाया के रूप में 70,320 करोड़ रुपये का भारी कर्ज है। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया की दुबारा गणना की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी। इससे कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार जल्द कदम उठाकर वीआई की कुछ बकाया राशि को इक्विटी में बदल सकती है।

कंपनी को मार्च 2026 तक सरकार को 29,000 करोड़ रुपये और मार्च 2027 तक 43,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं। यह भुगतान सितंबर 2025 में एजीआर बकाया पर दिए गए स्थगन (मोराटोरियम) की समाप्ति के बाद शुरू होगा। वीआई ने नवंबर के अंत तक जरूरी फंड जुटाने की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन एजीआर याचिका खारिज होने से यह प्रक्रिया अब और धीमी हो सकती है। बढ़ते कर्ज और रिलायंस जियो व भारती एयरटेल जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के कारण कंपनी के लिए स्थिति काफी खराब है। केंद्र सरकार, जिसके पास वीआई में 23.15 प्रतिशत हिस्सेदारी है, कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभा रही है। आदित्य बिड़ला ग्रुप (14.76 प्रतिशत) और वोडाफोन ग्रुप (22.56प्रतिशत) भी इसके सह-मालिक हैं।

कंपनी को अगले तीन सालों में 50,000-55,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) योजना को पूरा करना है। इसका उद्देश्य 4जी सेवाओं का विस्तार और प्राथमिक बाजारों में 5जी सेवाओं की शुरुआत करना है। लेकिन फंडिंग में देरी से योजना पर सवाल उठ रहे हैं। वीआई के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि बैंक सरकार से एजीआर बकाया पर राहत और बैंक गारंटी (बीजी) माफ करने को लेकर स्पष्टता मांग रहे हैं। जब तक इन पर स्थिति साफ नहीं होती, बैंक कर्ज देने से हिचक रहे हैं। कंपनी नकदी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के साथ कर्ज को इक्विटी में बदलने (डेब्ट-टू-इक्विटी कन्वर्जन) की योजना बना रही है। इसके अलावा, कंपनी 2022 से पहले खरीदे गए स्पेक्ट्रम पर बैंक गारंटी की शर्त हटाने की भी मांग कर रही है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट कर 675.65 अरब डॉलर पर

- गोल्ड रिजर्व भी 1.94 अरब डॉलर घटकर 67.81 अरब डॉलर हुआ

मुंबई (ईएमएस)। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ?पिछले सप्ताह 6.48 अरब डॉलर घटकर 675.65 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है, जो सप्ताह के दौरान कम हो गया है। रिजर्व बैंक के हाल ही में बयान के मुताबिक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 4.47 अरब डॉलर का घाटा होकर 585.38 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार का बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सीधा प्रभाव मुद्रा बाजारों पर होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की यह सूचना देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की भी गिरावट हुई है, जो 1.94 अरब डॉलर घटकर 67.81 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। अतः विदेशी मुद्रा भंडार में प्रमुख गिरावट और इसके प्रभाव की जांच आवश्यक है। साथ ही अंतरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 1.4 करोड़ डॉलर घटकर 4.30 अरब डॉलर पर आ गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण विकेन्द्रित विषय है जिसे अधिक जानकारी और विश्लेषण की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक की आंकड़ों के अनुसार यह सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि कारोबारी समृद्धि और अर्थव्यवस्था को लेकर मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना है। इसके लिए विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को समय रहते सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है।

वैश्विक ब्रोकरेज सीएलएसए का फिर भारत पर जोर, चीन में निवेश घटाया

- सीएलएसए ने दोनों देशों में निवेश की रणनीति में बदलाव करने का लिया है निर्णय

नई दिल्ली (ईएमएस)। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी सीएलएसए ने भारतीय शेयर बाजारों से निकलकर चीन में निवेश करने की घोषणा की है। ब्रोकरेज ने चीन में निवेश को अपनी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से में बदल दिया है। इसके बजाय, वह भारत में निवेश को बढ़ाने का मंजूरी दी है। सीएलएसए की रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी बाजारों में व्यापार की चुनौतियों के उभार के बाद, चीन में निवेश कम किया जा रहा है। इसके बजाय भारत में निवेश को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। व्यापारिक मामलों में चीन के विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए भारी विचारधारा बयान किया गया है, जो एक व्यापारिक युद्ध की संभावनाओं का सिग्नल दे रहा है। इस संदर्भ में, सीएलएसए ने दोनों देशों में निवेश की रणनीति में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

अक्टूबर की शुरुआत में भारत में निवेश को कम करते हुए, सीएलएसए ने चीन में निवेश को बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि, अब ब्रोकरेज कंपनी ने इस निर्णय को वापस लेते हुए भारत में निवेश में वापसी की घोषणा की है। सीएलएसए के इस रूपांतरण के साथ, व्यापारिक दुनिया में स्थिति में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। भारत में निवेश को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। व्यापारिक मामलों में चीन के विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए भारी विचारधारा बयान किया गया है, जो एक व्यापारिक युद्ध की संभावनाओं का सिग्नल दे रहा है। सीएलएसए का नया मुख्यालय भारत के वृद्धि और विकास के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्याज की कीमत में आई गिरावट

दिल्ली में प्याज की कीमत 67 रुपए किलो से 63 रुपए किलो गिरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में प्याज की कीमतों में मामूली गिरावट की खबर सभी को राहत देने वाली है। ?इस सप्ताह प्याज की कीमत 67 रुपए प्रति किलो से 63 रुपए प्रति किलो गिरी है। सरकार की उम्मीद है कि अगले 1-2 सप्ताह में और गिरावट आ सकती है। राजस्थान के अलवर में प्याज की फसल तैयार हो गई है, लेकिन दिवाली और छठ पर्व के दौरान मजदूरों की कमी के कारण फसल की कटाई में देरी हुई है।

सरकारी सहकारी समितियां नैफेड और एनसीसीएफ ने प्याज की सप्लाई बढ़ा दी है। सरकार ने इस साल 4.75 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया है। पिछले सप्ताह दो मालगाड़ियां प्याज लेकर दिल्ली पहुंची थीं और एक और मालगाड़ी नासिक से रवाना हो रही है। साथ ही, अब प्याज को मालगाड़ियों के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिससे लोकल प्याज की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। आजादपुर मंडी में प्याज व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कीमतों में स्थायी गिरावट की संभावना है, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि खरीफ की फसल आने के बाद कीमतें और भी कम हो सकती है।

एफपीआई ने बिकवाली करके 18,077 करोड़ के शेयर बेचे

- सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड में अब सिर्फ 240 आधार अंक का अंतर है

नई दिल्ली (ईएमएस)। विदेशी निवेशक (एफपीआइएस) के निवेश की दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे ही दोनों भारतीय ऋण और इक्विटी बाजारों से धीरे-धीरे निकाल रहे हैं। सीसीआईएल की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में एफपीआईएस ने शुद्ध बिकवाली करके सरकारी प्रतिभूतियों के 8750 करोड़ रुपये की बेची। अक्टूबर में इस आंकड़ा 5142 करोड़ रुपये था। विदेशी निवेशक इक्विटी बाजार से भी धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं, जिसमें नवंबर में 18077 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए हैं। दक्षिण एशियाई बाजारों में अवेक्षण करने वाले जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के ट्रेजरी और कैपिटल मार्केट्स के एक अ?धिकारी कहते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड में अब सिर्फ 240 आधार अंक का अंतर है, जिससे भारतीय बाजार के लिए निवेश कम हो सकता है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के संकेत हैं, जबकि डॉलर मजबूत हो रहा है जिससे भारतीय रुपया 84.41 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर उतार चढ़ाव देख रहा है। एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स के सीईओ कहते हैं कि एफपीआईएस की निवेश में जल्दी का उम्मीदवार नहीं है। हालांकि, बाजारों की समेकन अवधि में वृद्धि की उम्मीद है जिससे कंपनियों की आय बढ़ेगी और ब्याज दरों में कमी आ सकती है। उभरते बाजारों में भारत को एक आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है जिससे निवेशकों को स्थिरता की आशा है।

आगामी वर्षों में आईटी खर्च में तेजी से बढ़ोतरी का अनुमान

नई दिल्ली (ईएमएस)। गार्टनर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आईटी खर्च में आगामी वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी का अनुमान है। भारत का आईटी खर्च 2025 तक 160 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो 2024 से 11.2 प्रतिशत अधिक होगा। यह वृद्धि मुख्य रूप से एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ़्टवेयर बाजार में हो रही वृद्धि के कारण होगी।

गार्टनर के उपाध्यक्ष और विश्लेषक नवीन मिश्रा के मुताबिक, 2025 तक भारतीय सीआईओ जेनरेटिव एआई (जेनएआई) पर भी खर्च बढ़ाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए सीआईओ की अपेक्षाएं कम रहेंगी। इसके अलावा, भारतीय सीआईओ साइबर सुरक्षा, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों पर भी अधिक खर्च करेंगे। जेनएआई के उपयोग से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) में प्राइस प्रीमियम बढ़ने की संभावना है, जिससे इस क्षेत्र में भी तेजी आएगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2025 तक जेनएआई कैपेबिलिटी वाले 50 प्रतिशत से अधिक एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर प्राइस प्रीमियम से जुड़े होंगे। इसके अलावा, भारत में आईटी सेवाओं पर खर्च में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, खासकर क्लाउड, एप्लिकेशन और परामर्श से जुड़ी सेवाओं में। रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सेंटर सिस्टम पर खर्च 2025 में 4.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंटीग्रेशन के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है।

सीओपी-29 सम्मेलन : भारत समेत 132 ने किया सैन्य अभियान रोकने का आग्रह

अजरबैजान,(ईएमएस)। बाकू में 2024 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी-29) के तहत शांति, राहत और पुनर्प्राप्ति दिवस पर घोषणा की गई। इस दौरान प्रेसीडेंसी ने जानकारी दी कि भारत सहित 132 देशों ने सीओपी ट्रूस अपील में शामिल होने का फैसला लिया है। यह एक अहम वैश्विक पहल है जिसे एक हजार से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन हासिल करना है।

सीओपी ट्रूस का उद्देश्य सम्मेलन में शामिल देशों से सैन्य गतिविधियों को रोकने का आग्रह करना है। यह पहल ओलंपिक ट्रूस से प्रेरित है, जो ओलंपिक खेलों के दौरान शत्रुता को निलंबित करने के लिए बनाई गई थी। 1990 के दशक से यह पहल फिर से लागू की गई थी और 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर पारित किया गया। अब सीओपी-29 ने इस विचार को जलवायु संकट से निपटने के लिए अपनाया है, जिसमें सम्मेलन के दौरान सैन्य अभियानों को रोकने की अपील की है।

सीओपी ट्रूस की अवधि नवंबर 2024 तक प्रस्तावित की गई है, जो सीओपी-29 के पूरे कार्यकाल के साथ मेल खाती है। इस अवधि में युद्धविराम से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाएगा। युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों को रोकने के लिए यह पहल अहम है, क्योंकि वैश्विक सैन्य गतिविधियां और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन में इन सैन्य गतिविधियों का योगदान 5.5 फीसदी के आसपास है, जो विमानन और शिपिंग क्षेत्रों के संयुक्त उत्सर्जन से भी ज्यादा है। युद्धों के विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान, मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण, जलवायु संकट को और बढ़ा देते हैं। सीओपी ट्रूस पहल इस बात की जरुरत को बताता है कि शांति और पर्यावरणीय स्थिरता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास जरूरी है।

एलन मस्क ने की ईरानी राजदूत से सीक्रेट मीटिंग....चुनावी वादे पूरा करने जुटे ट्रंप

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिका में ईरानी राजदूत से मुलाकात की है। दोनों के बीच यह मीटिंग मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट का नया संयुक्त प्रमुख बनाए जाने से एक दिन पहले हुई।

अज्ञात सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि यह बैठक न्यूयॉर्क में राजदूत आमिर सईद इरावानी के निवास पर हुई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के तरीकों पर चर्चा करना था। रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है कि विदेश मंत्री पद के लिए नामित मार्को रुबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज, जो ईरान के कट्टर विरोधी हैं, को इस गोपनीय बैठक के बारे में जानकारी थी या नहीं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो ईरानी अधिकारियों के अनुसार यह बैठक सकारात्मक थी। मस्क ट्रंप की ओर से संभावित परदे के पीछे के वार्ताकार के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने मध्य पूर्व और यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का वादा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सत्ता के गलियारों में फेडरल खर्च को कम करने के काम की अपेक्षा कहीं अधिक अहम जिम्मेदारी निभाने वाले हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान, ट्रंप ने मस्क को बातचीत में शामिल किया, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी संपर्क में हैं। अमेरिका के तेहरान के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन मस्क के साथ एक निजी बैठक ने बातचीत का एक रास्ता निकाला है, इससे ईरान को एक अमेरिकी अधिकारी के साथ बैठक से बचने में मदद मिली। ट्रंप का पिछला कार्यकाल ईरान के खिलाफ सख्त कदमों के लिए जाना जाता है। ट्रंप की ओर से ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आई आरजीसी) के नेता कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया गया था।

ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्यों, जर्मनी और यूरोपीय संघ द्वारा किए गए परमाणु समझौते को रद्द किया था। उन्होंने कठोर आर्थिक प्रतिबंधों को दोबारा लागू कर दिया था, जो बड़े पैमाने पर अमेरिकी कंपनियों को ईरान में व्यापार करने से रोकते हैं। हालांकि भविष्य में दोनों देशों के बीच किस तरह के संबंध हो सकते हैं, यह कहना अभी फिलहाल मुश्किल है।

पुतिन से हुई बातचीत पर घिरे एलन मस्क, अमेरिकी सांसदों ने जताई चिंता

राजनीतिक हलकों में हलचल, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल से जांच की मांग

वाशिंगटन,(ईएमएस)। एलन मस्क जो स्पेसएक्स के मालिक हैं और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी भी हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य रूसी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के कारण जांच के घेरे में आ गए हैं। यह मामला उस समय सामने आया जब एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाए जाने की बात सामने आई। इस अहम सरकारी पद पर नियुक्ति से पहले मस्क द्वारा रूस के अधिकारियों से संपर्क किए जाने पर अमेरिकी संसद में चिंता जताई गई है।

रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बना हुआ हैं। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, और इस बीच एलन मस्क की पुतिन से अक्टूबर में हुई कथित बातचीत ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने पेंटागन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एलन मस्क और रूस के अधिकारियों के बीच बातचीत की जांच की मांग की है। सीनेटर जीन शाहीन और जैक रीड ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड और पेंटागन के महानिरीक्षक से आग्रह किया है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाए।

सांसदों ने संयुक्त पत्र में लिखा है कि यह चिंता का विषय हैं, खासकर तब जब एलन मस्क एक अमेरिकी विरोधी व्यक्ति और अमेरिकी सरकार के अरबों डॉलर के लाभार्थी माने जाते हैं। इस मामले पर उठे विवाद के बाद कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने पुतिन के साथ मस्क के संपर्क की गहन जांच की मांग की है। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि अगले साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनकी सरकार में मस्क को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस पर रिपब्लिकन पार्टी का रुख भी दिलचस्प होगा, क्योंकि वे मस्क को वाइट हाउस में बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। इस समय अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सत्ता है, और उनके लिए यह मुद्दा गंभीर हो सकता है।

इज़राइल और हिज़्बुल्लाह संघर्ष हुआ तेज, आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों पर बरसाए बम

तेल अवीव,(ईएमएस)। इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच जारी संघर्ष अब और खतरनाक हो गया है। शुक्रवार को इज़राइली सेना आईडीएफ ने बेरूत के रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले करके भारी बम बरसाए। धमाकों से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हमले में दर्जनों लोग की मौत हो गई है, लेकिन मौत के सटीक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों में इज़ारइली हवाई हमले में बेरूत के घनी आबादी वाले क्षेत्र में आईडीएफ ने हमला किया। इसमें कई इमारतें, जिनमें आवासीय फ्लैट, व्यापारिक केंद्र और पुलिस स्टेशन शामिल हैं, पूरी तरह तबाह हो गए।

वहीं हिज़्बुल्लाह भी इजराइली पर लगातार हमले कर रहा है। इज़राइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने सीमावर्ती इज़राइली शहर किर्यत बालिक पर रॉकेट दागे, जिसमें तीन विदेशी नागरिक के घायल होने की खबर है। इस संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका ने लेबनान की संसद को संघर्षविराम के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इज़राइल ने पिछले तीन दिनों से दक्षिणी लेबनान पर भारी बमबारी की है, जिससे हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक 3,200से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 14,200 से ज्यादा घायल हैं।

गाजा में हमास के साथ जारी जंग के बीच इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच यह नया मोर्चा पूरे क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों को देखते हुए संघर्षविराम की पहल को तेजी से अमल में लाना जरुरी है।

अर्थव्यवस्था सुधारने दिसानायके ने भारत से मांगा सहयोग, चीन को लगा झटका

कोलंबो,(ईएमएस)। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को संसदीय चुनावों में भारी बहुमत हासिल हुआ है, जिससे उनके आर्थिक सुधारों को मजबूती मिली है। उनकी पार्टी नेशनल पीपुल्स पॉवर्स (एनपीपी) ने 225 सीटों में से 159 सीटों पर जीत हासिल की है और उन्हें अब तक के कुल वोटों में 62 फीसदी समर्थन मिला है। वहीं विपक्षी नेता सजीत प्रेमदासा की पार्टी को केवल 18 फीसदी वोट मिले हैं।

चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रपति दिसानायके ने भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा से मुलाकात की और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत से सहयोग की अपील की। श्रीलंका के इस कदम से चीन को झटका लग सकता है, क्योंकि चीन की निगाहें लंबे समय से श्रीलंका पर हैं, अब श्रीलंका का रुख भारत के प्रति ज्यादा अनुकूल दिख रहा है।

भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को बधाई दी और कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, श्रीलंका के जनादेश का स्वागत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण है। 2022 से भारत ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान की, जो उनके लिए संकटमोचक साबित हुई। यह पहली बार है ब्रिटेन से मिली आज़ादी के बाद दिसानायके की पार्टी ने तमिल बहुल जाफना जिले में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जो इस चुनाव की एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। इस बदलाव से श्रीलंका और भारत के बीच रिश्तों में और प्रगाढ़ता की संभावना है।

लाखों लोगों को सरकारी नौकरी से निकालेगा अमेरिका

रामास्वामी, बोले- मस्क का तरीका अपनाएंगे, देश को बचाने के लिए ये जरूरी

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती का संकेत दिया है। रामास्वामी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वे मस्क के साथ मिलकर लाखों सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निकाल देंगे। वे इसी तरह से देश को बचाने जा रहे हैं।

रामास्वामी ने कहा कि अगर आप मस्क के काम करने के तरीके को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वे 'छेनी' की तरह नहीं, बल्कि 'आरी' के जैसे काम करते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी में उनका ये तरीका अपनाने जा रहे हैं। यह देखना काफी मजेदार होगा। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में रामास्वामी और टेस्ला चीफ इलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रभारी बनाया है। ट्रम्प ने सरकारी नौकरशाही को खत्म करने और सरकार के पैसे बचाने के लिए इस विभाग की शुरुआत की है।

अमेरिका के अच्छे दिन आने वाले हैं

हमें पिछले चार साल में यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका का पतन हो रहा है। हम प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पिछले सप्ताह जो कुछ हुआ है, उससे यही लगता है कि हम एक बार फिर से प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। विवेक ने कहा कि बहुत अधिक ब्यूरोकेसी का मतलब है कि इनोवेशन कम और खर्चे ज्यादा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन और बाकी एजेंसियों में ऐसी ही समस्याएं हैं। ऐसी एजेंसियां अपने फैसलों से नए आविष्कार नहीं होने देती और लागत को बढ़ाती है। इससे देश के विकास में रुकावट पैदा होती है। रामास्वामी ने कहा, अब अमेरिका में एक नई सुबह की शुरुआत होगी, जहां हमारे बच्चे बड़े होंगे और हम उन्हें सिखाएंगे कि आप कड़ी मेहनत के बलबूते ही अमेरिका में फिर से आगे बढ़ सकते हैं।

अब सबसे योग्य को ही नौकरी

अमेरिका में अब सबसे योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिलेगी, चाहे वह किसी भी रंग का क्यों न हो। रामास्वामी ने कहा कि हम देश में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली दिमाग को इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारे दौर का नया मैनहटन प्रोजेक्ट है। मैनहटन प्रोजेक्ट दरअसल अमेरिकी सरकार का एक प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर जर्मनी की नाजी सेना से पहले परमाणु बम विकसित करना था।

हर हफ्ते लाइवस्ट्रीम करेंगे मस्क और रामास्वामी

डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के कामों के बारे में जानकारी देने के लिए हर हफ्ते मस्क और रामास्वामी लाइवस्ट्रीम भी करेंगें। इस लाइवस्ट्रीम का नाम डोजकास्ट रखा गया है। इसमें अमेरिकी जनता को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के कामों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। टेस्ला चीफ इलॉन मस्क और बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने अमेरिका सरकार के नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी गई है।

आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए बढ़ाई मुसीबत, सेना प्रमुख की बढ़ी चिंता

इस्लामाबाद(ईएमएस)। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद से घिरा हुआ है। उसके लिए आतंकी संगठन टीटीपी ने कई तरह की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खुद सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का आतंकवाद सभी वैश्विक आतंकवादी संगठनों और उनके छद्म संगठनों का केंद्र बन गया है। इस्लामाबाद में मर्गल्ला डायलॉग 2024 के विशेष सत्र में शांति और स्थिरता में पाकिस्तान की भूमिका विषय पर उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीमा की स्थिति पर चर्चा करते हुए थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल मुनीर ने कहा कि पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए व्यापक सीमा प्रबंधन व्यवस्था लागू की गई है। इस संगोष्ठी का आयोजन इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटयूट (आईपीआरआई) की ओर से किया गया था।जनरल मुनीर ने कहा कि खवारिज का खतरा दुनिया भर के सभी आतंकवादी संगठनों और उनके समर्थकों के लिए एक केंद्र बन गया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादियों की ओर से किए जाने पर रोक लगाएगी और इस संबंध में सख्त कदम उठाएगी। मालूम हो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के आतंकवादियों के लिए खवारिज शब्द का प्रयोग करता है। बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गुरुवार को बम विस्फोट हुआ था। इसकी चपेट में आने से 5 लोग मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले के टप्पी दावर इलाके में हुआ, जिसमें कई अन्य लोग घायल हो गए।

किम जोंग उन को फिर सूझी सनक, खतरनाक हथियार बनाने का दिया आदेश

- रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने देगा आत्मघाती ड्रोन

सियोल,(ईएमएस)। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए देश में आत्मघाती ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का आदेश दिया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने र

सूरत में दुश्मन कोचिंग क्लास?, मुस्लिम बच्चों को गुमराह करने पर मैनेजर गिरफ्तार!

सूरत,16 नवंबर,

सूरत समाचार: सूरत में एक शख्स द्वारा सांप्रदायिक एकता को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। यह प्रक्रिया शहर में स्टार ट्रेक नामक एक कोचिंग क्लास के माध्यम से होने का पता चला है। इस कोचिंग क्लास द्वारा मुस्लिम बच्चों को गुमराह करने और सांप्रदायिक एकता को नष्ट करने का प्रयास किया गया था. जानकारी के मुताबिक, आरोपी सुलेमान शेख एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है और उसके दामाद के साथ चल रहे विवाद के कारण यह पर्चा वायरल हुआ है. पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया है.

सूरत में सुलेमान शेख नाम का एक कट्टरपंथी स्टार ट्रेक नाम से टयूशन क्लास चला रहा था. जिसकी आड़ में वह मुस्लिम बच्चों को एक खास समुदाय के खिलाफ भड़काता था। जिसके लिए उन्होंने एक पैम्फलेट भी जारी किया. इस पर्चे में उन्होंने कई भड़काऊ बातें कहकर मुस्लिम बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, स्थिति बिगड़ने से पहले ही सूरत पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया.

सूरत की लिंबायत पुलिस ने सुलेमान शेख को गिरफ्तार कर पूछताछ की. आरोपी का दावा है कि उसका अपने दामाद से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। चूंकि पुलिस अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए आगे की जांच की गई है। गौरतलब है कि ये सुलेमान शेख एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं. इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस मामले में कोई और भी शामिल है या नहीं.

इस पैम्फलेट में सुलेमान शेख ने कक्षा 1 से 12 तक टयूशन के लाभ के साथ-साथ अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी. जिसमें कई विवादित घटनाओं का भी जिक्र किया गया.

पैम्फलेट में बताई गई अन्य सेवाओं में मुस्लिम विरोधी संगठनों के खिलाफ खड़े होने की तरकीब, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिव सेना जैसे संगठनों को जड़ से खत्म करने की तरकीब, अपने बच्चों को बजरंग दल और अन्य संगठनों से दूर रखने की तरकीब, अलीम दीन के साथ हर महीने चर्चा मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने, कुरान शरीफ पढ़ाने, एडम आर्मी में शामिल होने के साथ-साथ शरिया कानून के बारे में जानकारी देने के बारे में होती थी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि इस कक्षा में केवल मुस्लिम बच्चे ही प्रवेश कर सकते हैं। पैम्फलेट में दावा किया गया है कि टयूशन फीस का 20 फीसदी पैसा धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा.

नर्मदा में नहाते समय पिता-पुत्र डूबे; एक और किशोर का शव मिला

सूरत,16 नवंबर,

भारचभरच तालुका के शुकलतीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा के 6 दिवसीय मेले और उत्सव के साथ-साथ नर्मदा तट यात्रा के अंतिम दिन नर्मदा में स्नान करते समय तीन लोग डूब गए, जिनमें से एक किशोर का शव मिला है, जबकि लापता पिता की तलाश जारी है। और बेटा जो डूब गया. यह त्रासदी नर्मदा नदी के किनारे रेत खनन के कारण बड़ा गड्ढा बनने और उसमें डूबने से हुई थी।

देवदिवाली, शुकलतीर्थ में कार्तिकी पूर्णिमा के 6 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन है, जो पूरे गुजरात से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। आज आखिरी दिन भी नर्मदा नदी के किनारे जात्रा जारी रहने के बावजूद रेत खनन जारी रहा. मेले के बाद स्नान के महत्व के कारण ही नर्मदा स्नानार्थी नदी में डुबकी लगाते हैं। कल एक व्यक्ति डूबा था, जबकि आज तीन लोग डूब गये. जिसमें 11 साल के बच्चे का शव मिला. कल सूरत का सचिन नाम का युवक नर्मदा नदी में नहाते वक्त डूब गया. आज भर्रीच के पश्चिमी भाग वेजलपुर के निज़ामवाड़ी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शुक्लतीर्थ की यात्रा पर गए।

जिसमें निज़ामवाड़ी के मिस्त्री परिवार के लोग भी शामिल हुए. नदी में बड़े पैमाने पर हो रहे बालू खनन के मुद्दे पर मिस्त्री परिवार के तीन डूबे लोगों और एक मृतक के परिजनों ने हंगामा किया.

भर्राच सिविल अस्पताल में मृतक किशोर के परिवार सहित अन्य लोग भी पहुंचे और आंखों में आंसू के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया। वसंतभाई मिस्त्री (45 वर्ष), बिनीत मिस्त्री (17 वर्ष) दोनों लापता हैं। जबकि निशांत मिस्त्री (उम्र 11 वर्ष) का शव मिला है.

वराछा में रहने वाले अधेड़ से झगड़े के बाद महिला ने आत्महत्या कर ली

सूरत,16 नवंबर

सूरत में आत्महत्या के पांच मामलों में, एक महिला, डिंडोली में दो व्यक्तियों, अमरोली में एक युवक और रांदेर में एक बूढ़े व्यक्ति ने वराछा में अश्वनीकुमार रोड पर एक लिविंग रूम में रहने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली।

सिविल एवं स्मीमेर अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार वराछा के अश्वनीकुमार रोड पर रहने वाली 45 वर्षीय शोभनाबेन चौधरी ने कल देर रात घर में पंखे से साड़ी का फंदा बांधकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शोभनाबेन अपने परिवार से अलग दूसरे घर में मिथुन नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ रह रही थीं। हालाँकि, अब शोभनाबेन और मुथन में झगड़ा हो गया। बाद में संभव है कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि शोभनाबेन लगातार मानसिक तनाव से जूझ रही थीं. जबकि शोभनाबेन और मिथुन रोल पुलिस के तौर पर काम कर रहे थे. लेकिन फिलहाल शोभनाबेन काम नहीं कर रही थीं. उसके दो भाई हैं.

एक अन्य घटना में, डिंडोली में जलाराम सोसायटी में रहने वाले 55 वर्षीय पंडित बुद्ध ठाकर को 13 तारीख की सुबह घर पर एसिड निगलने के बाद इलाज के लिए स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया। जहां बीती दोपहर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पंडित महाराष्ट्र के जलगांव का मूल निवासी था। उनकी एक बेटी और दो बेटे हैं। उन्होंने बॉम्बे मार्केट में चौकीदार के रूप में काम किया। डिंडोली में गौरव ने एसिड निगल लिया, युवक ने फंदा, अमरोली में युवक और रांदेर में बुजुर्ग ने फंदा खाकर अपनी जिंदगी काट ली। संभव है कि उचित काम न मिलने पर वे अवसादग्रस्त हो गए हों इसलिए यह कदम उठाया गया हो। तीसरी घटना में, महाराष्ट्र के मूल निवासी और वर्तमान में डिंडोली के ठाकोरनगर में रहने वाले 36 वर्षीय मोरेश्वर हेराजी नंदनवार ने शुक्रवार सुबह रसोई में पंखे से पर्दा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अभिलेखागार में काम कर रहा था.

चौथी घटना में, अमरोली के कोसाड स्थित एसएमसी आवास में रहने वाले 32 वर्षीय मुक्तार मैकुदीन शेख ने कल शाम घर में पंखे के साथ कपड़े का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनके दो बेटे और एक बेटी है. वह एक फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे थे. पांच घटनाओं में रांदेर के पालनपुर पाटिया स्थित दिनदयाल सोसायटी में रहने वाले 65 वर्षीय नरेंद्रभाई गोविंदभाई रांदेरिया ने शुक्रवार सुबह घर में रसोई में पंखे से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। उनकी दो बेटियां और एक बेटा हीरों का काम करते हैं। वह सेवानिवृत्त जीवन जी रहे थे।

रिफाइनरी ब्लास्ट मामला: टैंक में लगी आग से एफएसएल टीम ने लिए 5-5 सैंपल, जांच के बाद सौंपेगी रिपोर्ट

वड़ोदरा,16 नवंबर,

वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी में आग लगने के मामले की जांच शुरू हो गई है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विभाग की मदद ली गई है. जिसकी रिपोर्ट जल्द ही फॉरेंसिक विभाग पुलिस को सौंप देगा. जिसके बाद घटना की असली वजह सामने आएगी.

आग के सही कारण का पता लगाने और भविष्य में एहतियाती कदम उठाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों से सलाह ली गई है।

फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने दो दिनों तक ऑपरेशन चलाया और टैंक नंबर 68 और 69 से प्रत्येक से पांच नमूने लिए। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने रिफाइनरी से टैंक और केमिकल से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी हासिल की. जल्द ही वे पुलिस को रिपोर्ट सौंपेंगे।

गुजरात रिफाइनरी में पेट्रोल टैंक में जोरदार विस्फोट से एक किमी का इलाका दहल उठा। इस घटना में बेकाबू आग के कारण बगल का दूसरा टैंक भी आग की चपेट में आ गया, जिससे वह भी धमाके के साथ फट गया. पूरी घटना में दो संविदा कर्मियों की मौत हो गयी.

टयूशन से घर लौट रही कॉलेज की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या, जांट में जुटी पुलिस

वलसाड (ईएमएस) जिले के मोतीवाडा के निकट कॉलेज की एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। छात्रा को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पैनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। जिसके बाद पारडी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि युवती वलसाड जिले की पारडी की कॉलेज की छात्रा थी और उदवाडा में टयूशन करने गई थी। टयूशन खत्म होने के बाद युवती अपने घर की ओर लौट रही थी। उस वक्त युवती किसी के साथ मोबाइल पर बात कर रही थी। जिसके बाद युवती के साथ कुछ अनहोनी आशंका उससे बात करने वाले परिचित ने उसकी छोटी बहन को जानकारी दी। युवती के साथ अनहोनी की जानकारी मिलते ही बहन उसकी तलाश मोतीवाडा क्षेत्र में पहुंचे। मोतीवाडा के मैदान में युवती बेहोशी की हालत में मिली। युवती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती के मृतदेह का पैनल पीएम करवाया गया। जिसमें खुलासा हुआ कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद हत्या की गई। इस खुलासे के बाद पारडी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक की बहन समेत अन्य परिचितों की मौजूदगी में घटनास्थल के आसपास जांच की। जिहां से पुलिस को एक बैग समेत कुछ सबूत मिले हैं। हांलाकि पुलिस को अब तक युवती का मोबाइल नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने लड़की का मोबाइल फोन ढूंढने के लिए भी गहन जांच में जुट गई हैं। फिलहाल मृतक बच्ची के साथ किसने दुष्कर्म किया और हत्यारा कौन है? इसे लेकर कई रहस्य बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टयूशन से घर जाते वक्त लड़की संदिग्ध हालत में मिली? यही कारण है कि लड़की की मौत का रहस्य बरकरार है। हत्यारा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। दूसरी ओर परिजनों ने अभी तक किसी पर आशंका नहीं जताई हैं। ऐसे में पुलिस के लिए दुष्कर्म और हत्या का मामला किसी चुनौती से कम नहीं हैं। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं।

वडोदरा में अटलादरा-मांजलपुर रेलवे ओवर ब्रिज का काम पूरा होने में अभी तीन महीने और लगेंगे

वडोदरा ,16 नवंबर

वडोदरा नगर निगम द्वारा अटलादरा-मांजलपुर रोड लाइन पर मांजलपुर दरबार चौक से अटलादरा तक मुंबई अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन के ऊपर 36 मीटर रोड लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज का काम पिछले चार-पांच साल से चल रहा है। करीब 41 करोड़ की लागत से. चूंकि पुल का काम अभी भी लंबित है, इसलिए इसे पूरा होने में तीन से चार महीने लगने की संभावना है।

रेलवे विभाग द्वारा पुल के मध्य भाग के निर्माण के लिए पहले रेलवे द्वारा वर्क ऑर्डर दिया गया था, लेकिन पानी की लाइन सहित अन्य कारणों से डिजाइन में संशोधन किया गया था। इस संशोधित डिजाइन को रेलवे विभाग से मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया गया. इस बीच बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होने के कारण देरी हुई. रेलवे ने पुल के रेलवे हिस्से का स्पैन अक्टूबर में पूरा कर लिया है, लेकिन निगम पुल के एप्रोच वाले हिस्से को इस स्पैन से जोड़ना बाकी है। यह कार्य पूरा होने पर कारपेटिंग का कार्य किया जाएगा।

चूंकि ब्रॉडगेज लाइन पर रेलवे का ट्रैफिक लगातार चल रहा है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए परिचालन करना पड़ा. इस पुल का काम राज्य सरकार और रेलवे विभाग ने 50-50 फीसदी लागत हिस्सेदारी के साथ किया है. पुल की लंबाई लगभग 797.90 मीटर, चौड़ाई 16.80 मीटर है, जिसमें 7.50 मीटर के दो कैरिज-वे शामिल हैं। चार साल पहले निगम में पुल के काम का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। टेंडर में कार्य की समय सीमा मानसून को छोड़कर 18 माह रखी गयी थी. हालांकि, इस पुल के लिए जमीन अधिग्रहण का सवाल भी निगम के लिए बाधा था. जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण पुल का काम रुका हुआ था. 2022 के अंत में निगम ने रोड लाइन में आने वाली जमीन के मालिकों के साथ बैठक की. जमीन में प्लॉट को वैध करने के बाद मालिकों को 60 फीसदी हिस्सा वैध कर दिया गया. उन्होंने जनता के लिए काटी गई जगह का 40 प्रतिशत हिस्सा निगम को सौंप दिया। अत: संपादन की समस्या दूर हो गई। चालू वर्ष के बजट के समय निगम ने यह भी कहा था कि पुल का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जायेगा. इस पुल के बनने व सड़क खुलने से मांजलपुर व शहरी क्षेत्र के लोगों को अटलादारा, कलाली व पदरा जाना आसान हो जायेगा.

वडोदरा में खोदे गए गड्ढे में बैरिकेड नहीं लगाने से बाइक चालक गिरा

वडोदरा:,16 नवंबर

वडोदरा जिले की वाघोडिया नगर पालिका के अनाड़ी प्रशासन का मामला सामने आया है. देर रात एक अज्ञात बाइक सवार सार्वजनिक सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिर गया। बाइक चालक को स्थानीय लोगों ने बचाया और गंभीर रूप से घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

वडोदरा जिले के वाघोडिया विकास पथ पर देर रात वाघोडिया नगर पालिका द्वारा खोदे गए गड्ढे के कारण एक बाइक सवार की जान खतरे में पड़ गई। नगर पालिका द्वारा पानी की लाइन की मरम्मत के लिए सार्वजनिक सड़क पर बड़ा गड्ढा खोदा गया था। हालांकि, रात के समय एक अज्ञात बाइक सवार जिसने गड्ढे के चारों ओर बैरिकेड नहीं लगाया था, वहां से गुजरते समय गड्ढे में गिर गया। बाइक सवार खाई में गिर गया और स्थानीय लोगों ने उसे बचाया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें 108 के माध्यम से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

वाघोडिया नगर पालिका का संचालन वर्तमान में प्रशासक मामलतदार हितेंद्रसिंह गोहिल द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका के अनगढ़ प्रशासन के कारण पिछले चार-पांच दिनों से खोदे गए गड्ढे से सड़क के एक तरफ से यातायात संचालित होने पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है। जिससे हादसा हो जाता है। लाखों रुपये की लागत से तैयार किया गया विकास पथ जगह-जगह खोदाई से जर्जर हो गया है। देर रात हुए हादसे के बाद सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं.

16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सूरत,16 नवंबर

कोर्ट ने शिकायतकर्ता और पीड़ित के बीच हुई लड़ाई में झूठी शिकायत दर्ज करने के बचाव को खारिज कर दिया: लड़की को 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और पीड़ित के बीच हुई लड़ाई में झूठी शिकायत दर्ज करने के बचाव को खारिज कर दिया: लड़की को 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश अतुलकुमार आर. पटेल ने तीन साल पहले वराछा क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले 20 वर्षीय आरोपी युवक को पॉक्सो के उल्लंघन का दोषी पाया अधिनियम, 20 वर्ष कठोर कारावास, कुल 20 हजार जुर्माना, न देने पर दो वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास। कारावास और पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

24-1-2021 को, माँ ने भावनगर जिले के शिहोर ताना गाँव के मूल निवासी 20 वर्षीय आरोपी बिपिन वालजी भाई चौहान के खिलाफ 16 वर्षीय 6- के साथ जबरदस्ती करके इ्ध्एए्ध अधिनियम का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज की। एक माह की बेटी की शादी कर दी और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जिसके मुताबिक शिकायतकर्ता मां और उसका पति अपने मायके चले गए हैं अपनी नाबालिग बेटी को वराछा में रहने वाले डियर डेरानी के घर भेज दिया। इस बीच, आरोपी बिपिन चौहान, जो शिकायतकर्ता का दूर का रिश्तेदार है, ने शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी का लालच देकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया।

इस मामले में वराछा पुलिस द्वारा जेल भेजे गए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान आरोपी के बचाव में मुख्य रूप से पीड़िता और आरोपी के बीच दूर के रिश्तेदार का रिश्ता था और पीड़िता के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी इसके विरोध में सरकार की ओर से एपीपी संतोष के गोहिल ने कुल 16 गवाह और 20 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये. अदालत ने आरोपी को सभी कथित अपराधों का दोषी पाया, इसलिए बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी की हाल ही में शादी हुई थी और पूरे मामले के तथ्यों को देखते हुए, युवा आरोपी की जिम्मेदारी बनती दिखाई दी दूर का रिश्तेदार होते हुए भी वर्तमान कृत्य बचकाना, महिला विरोधी एवं समाज विरोधी था तथा भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित न करने वाला घिनौना कृत्य किया। होय ने अधिकतम सजा की मांग की, इसलिए अदालत ने आरोपी को धारा-4 सहपठित धारा 3(ए)(सी) और धारा-6 सहपठित धारा-5(एल) के उल्लंघन के लिए उपरोक्त कठोर कारावास, जुर्माना और कारावास की सजा सुनाई। (यू) पॉक्सो एक्ट के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.

राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने के लिए वलसाड जिला कलेक्टर नैमेश दवे की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित

वलसाड,16 नवंबर

गुजरात प्रेस अकादमी, गांधीनगर और जिला सूचना कार्यालय, वलसाड की संयुक्त पहल से इछाबा अनाविल समाजनी वाडी, तिथल रोड, वलसाड में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने के लिए एक प्रेस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर श्री नैमेश दवे सहित गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया।

इस प्रेस सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर श्री नैमेश दवे ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्व को समझाते हुए कहा, मैं उन मीडियाकर्मियों की सराहना करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का कठिन काम कर रहे हैं। गंभीर स्थिति. पत्रकार प्रशासनिक तंत्र द्वारा रह गई किसी भी चूक की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि बेहतर काम किया जा सके। उन्होंने धरमपुर में मनाये गये जनजाति गौरव दिवस समारोह की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार बंधुओं को बधाई दी। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि वलसाड जिले के 470 में से 333 गांव ऐसे हैं जिनमें पूरा आदिवासी समुदाय रहता है. इस गांव में रहने वाले करीब 11 लाख आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार अगले पांच साल तक उन्हें पीएम जनमन के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ देगी. उमरगाम, धरमपुर और कपराडा में विकास रथ के माध्यम से भी लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने सभी मीडिया कर्मियों से चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की.

इस अवसर पर वरिष्ठ वक्ता के रूप में उपस्थित सेवानिवृत्त संयुक्त सूचना निदेशक सेसिल क्रिस्टी ने पारंपरिक मीडिया से लेकर वर्तमान मीडिया में आये बदलावों पर प्रकाश डाला और कहा कि इंटरनेट के आगमन के बाद मीडिया का स्वरूप भी बदल गया है। समाचारों को शीघ्रता से प्रसारित करने की होड़ भी बढ़ गई है। नवोदित पत्रकारों को दिशा निर्देश देते हुए श्री क्रिस्टी ने कहा कि पत्रकार जनमत संग्रह के निर्माता होते हैं. एक पत्रकार का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कई वर्षों से मीडिया से जुड़े पत्रकारों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वर्तमान समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसलिए पत्रकारों को लगातार अपडेट रहने की जरूरत है.

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा घोषित ठप्रेस की बदलती प्रकृतिठ विषय पर वरिष्ठ वक्ता और गुजरात गार्जियन दैनिक के संपादक मनोजभाई मिस्त्री ने कहा कि एक पत्रकार की भूमिका एक मील के पत्थर की तरह है। पत्रकारों को अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। चाहे कितने भी बदलाव हों, विश्वसनीयता का होना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर देश के चारों स्तंभ मजबूत होंगे तो लोकतंत्र को कोई झटका नहीं लगेगा। श्री मिस्त्री ने पत्रकारों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, हमने जो पेशा अपनाया है, उसे ईमानदारी से निभायें. ऐसे सेमिनार पत्रकारों के बीच माहौल साफ करने के लिए सकारात्मक साबित होते हैं।

प्रेस सेमिनार में पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किये. राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह के कार्यक्रम में सूरत क्षेत्रीय सूचना कार्यालय के संयुक्त सूचना निदेशक श्री अमित गढ़वी ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बताते हुए कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। जिला सूचना कार्यालय की सूचना उपनिदेशक सुश्री भावना वसावा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन प्रतीकभाई कोटक ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विकास अधिकारी श्री अतिराग चपलोत, सूरत क्षेत्रीय कार्यालय के उप सूचना निदेशक श्री उमेश बाविसा, जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र तथा जिला सूचना कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कपराड़ा के प्रगतिशील युवा किसान को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सम्मानित किया

वलसाड,16 नवंबर

गांधीनगर के गिफ्ट सिटी क्लब में विकसित गुजरात 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में जिले में सराहनीय कार्य करने वाले कपराडा तालुका के करजुन गांव के प्रगतिशील युवा किसान रघुनाथ भोया को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हाथों सम्मानित किया गया। वर्तमान में, गांव-गांव तक प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने के लिए, रघुनाथ भोया ने आत्मा परियोजना के सहयोग से कपराडा, धरमपुर, पारदी और चिखली तालुका में 1500 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कृषि क्षेत्र में कदम रखा और पुरस्कार भी जीते। वर्तमान में वह प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के साथ-साथ कपराडा तालुका के सह-समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। राज्यपाल द्वारा सम्मानित किये जाने पर वलसाड जिले के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी.

सर्दियों में स्कूल निश्चित रंग के गर्म कपड़े पहनने के लिए बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते

अहमदाबाद,16 नवंबर

अहमदाबाद डीईओ परिपत्र: राज्य वर्तमान में सर्दी और गर्मी के दोहरे मौसम का अनुभव कर रहा है, सुबह और रात में ठंडक और दोपहर में गर्मी। हालाँकि, सर्द मौसम की शुरुआत के साथ, शिक्षा विभाग ने अहमदाबाद के सभी स्कूलों को एक नोटिस जारी किया है कि छात्रों को वर्दी के अलावा रंगीन यानी गर्म कपड़े पहनने की अनुमति दी जाए।

राज्य में अहमदाबाद समेत कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ ठंड बढ़ गई है. अहमदाबाद जिला शिक्षा विभाग द्वारा छात्र के स्वास्थ्य और हित को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसमें ठंड के मौसम में छात्र-छात्राओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने घरों से जो भी गर्म कपड़े लाएंगे उसे स्वीकार कर लें।

मौसम वैज्ञानिक अंबालाल पटेल ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में प्रदेश में लोगों को स्वेटर और कंबल तैयार कर लेने चाहिए. उन्होंने उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण इस बार राज्य में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने की संभावना जताई है. अंबालाल पटेल के मुताबिक, जब तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा, तब तक ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। अभी पश्चिमी विक्षोभ आएगा लेकिन मजबूत नहीं।

हालांकि 17 नवंबर के बाद से गर्मी कुछ हद तक कम हो जाएगी और ठंड बढ़ जाएगी. इस बीच, उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास जा सकता है। इस महीने के अंत में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके चलते देश के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना रहेगी. इसलिए न्यूनतम तापमान में तेजी से कमी आएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक, स्कूल विद्यार्थियों को इस रंग के गर्म कपड़े अनिवार्य रूप से पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. इसके अलावा, अगर स्कूल यूनिफॉर्म में स्वेटर शामिल हैं, तो उन्हें विशिष्ट दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर न करें। जिसमें अगर कोई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प के खिलाफ जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

पांच महीने पहले खरीदी डेढ़ करोड़ की लैंड रोवर कार आग में जलकर स्वाहा

वडोदरा (ईएमएस) डेढ़ करोड़ रुपए देकर पांच महीने पहले खरीदी गई लैंड रोवर कार आग में जलकर खाक हो गई। घटना के बाद इतनी महंगी कार में सुरक्षा केसवाल उठाए जा रहे हैं। अगर डेढ़ करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी सुरक्षा नहीं हैतो ऐसी कार किस काम की? लैंड रोवरकार में आग लगने की घटना वडोदरा से सामने आई हैं। वडोदरा के कारेलीबाग क्षेत्र की पराग सोसायटी में पार्क रु. 1.50 करोड़ कीलैंडरोवर की डिफेन्डर में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही पल में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में आग घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी।

वापी में गुंजन चार रोड के पास तेज रफ्तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई

वलसाड,16 नवंबर

40 वर्षीय सुनील सूबेदारदीन वापी के भड़कमोरा स्थित सुलपाड़ में रहते हैं। 8 नवंबर 2024 को शाम 4-15 बजे जीआईडीसी गुंजन चार रोड, वापी के पास सड़क पार करते समय वैशाली ब्रिज की ओर से आ रहे आइसर टेम्पो क्र. जीजे - 15 - एटी - 1543 के चालक ने अपना वाहन पूरी गति और लापरवाही से चलाया और सुनील सूबेदारिन को टक्कर मारकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल सुनील को इलाज के लिए वापी के हरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान रात 9 बजकर 55 मिनट पर उनकी मौत हो गई. मृतक मध्यम कद काठी का था और उसका कद पांच फीट तीन इंच था।

मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल ने कैंसर की रोकथाम, शुरुआत में पहचान और उपचार को सुलभ बनाने के संकल्प के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया

मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल ने बड़े गौरव के साथ 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया, तथा इस अवसर को कैंसर की रोकथाम और शुरुआती चरण में पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उपचार के कारगर विकल्पों को सुलभ बनाने की जरूरत के लिए समर्पित किया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हम सभी को कैंसर के खिलाफ जारी बेहद महत्वपूर्ण संघर्ष की याद दिलाता है, और इस बार को भी सामने लाता है कि समुदायों पर इस बीमारी के प्रभाव को न्यूनतम करना हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। साल 2024 का राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, कैंसर की शुरुआती चरण में पहचान एवं रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उपचार को सुलभ बनाने की थीम पर आधारित है। कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर, मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल ने लोगों एवं समुदायों को कैंसर से बचाव हेतु एहतियाती कदम उठाने के लिए जरूरी जानकारी तथा संसाधनों के साथ सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, अस्पताल ने समय पर जाँच और बेहतर गुणवत्ता वाले उपचार को सुलभ बनाने की अहमियत पर भी बल दिया, ताकि मरीजों के लिए परिणामों को बेहतर बनाया जा सके और कैंसर से जुड़ी मृत्यु-दर को कम किया जा सके।

बीते कुछ सालों में मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरकर सामने आया है, जिनके लिए दूसरे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। यह अस्पताल कैंसर के इलाज की अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और उन्हें उपयोग में लाता है, जहाँ मरीजों को उपचार के बेहतर परिणामों के लिए रोबोटिक ट्रीटमेंट के विकल्प की पेशकश की जाती है। इस अस्पताल ने रोबोटिक सिस्टम की मदद से, रोबोट की सहायता से अपनी तरह की पहली स्तन कैंसर सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा करके शहर में चिकित्सीय उत्कृष्टता की मिसाल कायम की है।

मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी प्रमुख, डॉ. भावेश पारेख ने कहा, ठराष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस अपनी सेहत के लिए एहतियाती कदम उठाने की अहमियत की याद दिलाता है।